



विक्रम संवत् 2081 • आषाढ /श्रावण मास(05) • 01 जुलाई 2024 • मूल्य : 23 रु.

# चरैवेति

चुनाव 2024  
सफल रही भाजपा  
की रणनीति



» प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 18वीं लोकसभा के पहले सत्र से पहले मीडिया को संबोधित किया।



» प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वाराणसी में गंगा पूजन किया।



» भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जे.पी.नड्डा जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग में भाग लिया।



» प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की।



» प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया।



» केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सैनिकों के साथ योग किया।



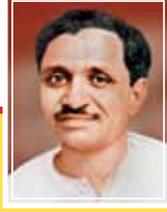
» केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया।



» प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूर्व उपराष्ट्रपति श्री एम. वैकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर तीन पुस्तकों का विमोचन किया।



वर्ष-56, अंक : 05, भोपाल, जुलाई 2024



हमारे प्रेरणास्रोत

पं. दीनदयाल उपाध्याय

ध्येय बोध

हमें एक ऐसा भारत बनाना है जो हमारे पूर्वजों के भारत से भी अधिक गौरवशाली हो।

- पं. दीनदयाल उपाध्याय

सचिव, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक  
संजय गोविंद खोचे\*

सहायक सम्पादक  
पं. सलिल मालवीय

व्यवस्थापक  
योगेन्द्रनाथ बरतरिया

मोबा. नं. 09425303801

पं. दीनदयाल विचार प्रकाशन म.प्र. के लिये मुद्रक एवं प्रकाशक संजय गोविंद खोचे द्वारा पं. दीनदयाल परिसर, ई-2, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016 से प्रकाशित  
एवं एम. पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेस-II, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा - 201 305 से मुद्रित.

संपादकीय पता

पं. दीनदयाल परिसर,

ई-2, अरेरा कालोनी, भोपाल- 462016

e-mail:charevetibpl@gmail.com

web site:www.charaiveti.org

मूल्य- तेईस रुपये

\*समाचार चयन के लिए पी.आर.वी.एकट के तहत जिम्मेदार

# अनुक्रमणिका

संपादकीय • संजय गोविन्द खोचे

04

■ तीसरी सफलता- कठोरतम तप का परिणाम

कवर स्टोरी

05

■ 2024 चुनाव-सफल रही भाजपा की रणनीति

05



■ आपात काल : काला अध्याय 08

» आपातकाल प्रजातंत्र का गला घोटने का कुत्सित...  
» आपातकाल "काला दिवस" अमित शाह...

■ आपात काल : काला अध्याय - डॉ. मोहन यादव 11

» आपातकाल-भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय...

■ आपात काल : काला अध्याय - तरुण चुध 13

» आपातकाल: अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक व अत्याचार का काल...

■ जीत की समीक्षा : 15

» भाजपा के कार्यकर्ता सजग प्रहरी : विष्णुदत्त शर्मा  
» ऐतिहासिक विजय : शिवप्रकाश जी

■ अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस : 17

» योग से समाज में सकारात्मक बदलाव - पीएम मोदी...  
» मोदी जी ने योग को लोकप्रिय बनाया : डॉ. मोहन यादव

■ G-7 समिट : 20

» संकल्प - 2047 तक विकसित भारत...

■ विकसित भारत का मजबूत स्तंभ 21

» तीसरी आर्थिक ताकत बनाने में कृषि की बड़ी भूमिका...

■ 18वीं लोकसभा 23

» 18वीं लोकसभा सपनों को पूर्ण करेगी - पीएम मोदी...

■ जन्म दिवस 24

» डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी: एक आदर्श नेता...

■ बहुआयामी व्यक्तित्व: डॉ. मुखर्जी 25

» डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी-एकता एवं अखंडता के अग्रदूत...

» डॉ. मुखर्जी - निष्काम, निस्वार्थ, निष्कपट राज-योगी

» स्वत्व, स्वाभिमान और राष्ट्र के लिए जीवन का बलिदान...

■ मन की बात 31

» चर्चा संस्कृति, इतिहास और विकसित भारत की

■ आलेख : शिवप्रकाश 35

» सुशासन के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज

■ आलेख : डॉ. मोहन यादव 37

» रानी दुर्गावती - जनकल्याण और शौर्य का शिखर

■ जन्म दिवस 39

» अमर शहीद : चन्द्रशेखर आजाद

» सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रणेता तिलकजी

■ विचार प्रवाह : पं. दीनदयाल उपाध्याय 41

» क्या है सेक्यूलरिज्म?...

## • मुख्य व्रत-त्यौहार

2. योगिनी एकादशी व्रत 3. प्रदोष व्रत 4. शिव चतुर्दशी व्रत 5. हलहारिणी अमावस्या, स्नानदान श्राद्ध अमावस्या 6. गुप्त नवरात्रारम्भ 7. चन्द्रदर्शन, रथयात्रा 9. अं. विनायकी चतुर्थी व्रत 13. वैवस्वत पूजा 15. भडली नवमी, नवरात्रा स. 16. आशा दशमी 17. देवशयनी/ हरिशयनी ग्यारस व्रत 18. वासुदेव द्वादशी, प्रदोष व्रत 19. विजया पार्वती, मंगला तेरस 21. स्नानदान व्रत एवं गुरू पूर्णिमा 22. श्रावण सोमवार व्रत प्रारम्भ 24. गणेश चतुर्थी व्रत 25. मौना पंचमी, नाग मरूस्थले 27. शीतला सप्तमी 31. कामिका एकादशी व्रत

## • मुख्य जयंती-दिवस

1. डॉक्टर्स एवं सी. ए. दिवस 6. पं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती 11. विश्व जनसंख्या दिवस 17. विट्ठलवारी महोत्सव 19. डॉ. खूबचंद बघेल ज. 23. चन्द्रशेखर आजाद जयंती, लोकमान्य तिलक जयंती 25. प्राणनाथ परमधाम वास दिवस 27. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम पु. ति. 31. उधमसिंह शहीदी दिवस



यह जनादेश बीजेपी-एनडीए गठबंधन के लिए ऐतिहासिक विजय है। साठ वर्षों से चली आ रही परिपाटी के अनुसार 2024 का चुनाव विपक्ष के लिए एक सुनहरा अवसर था। क्योंकि किसी सरकार का लगातार तीसरी बार सरकार में आना लोकतंत्र में बहुत ही कठिन कार्य होता है। फिर भी विपक्ष नाकामयाब क्यों रहा? विपक्ष लगातार तीसरे चुनाव में भी जनता का भरोसा क्यों नहीं जीत पाया?

## तीसरी सफलता- कठोरतम तप का परिणाम

**लोकसभा** चुनाव 2024 में मतदाताओं ने अपना निर्णय सुना दिया है। लोकतंत्र में मतदाताओं का निर्णय ही सर्वोपरि होता है तथा लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष की अपनी-अपनी भूमिका स्पष्ट हैं। भूमिकाओं का जिम्मेदारी से निवाहन लोकतंत्र व जनता की अपेक्षा है। चुनाव में सरकार व विपक्ष का आकलन उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर मतदाताओं के द्वारा होता है। मतदाताओं ने 60 वर्षों के बाद किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का जनादेश दिया है। सोचिए, साठ वर्षों से कोई भी सरकार तीसरी बार जनादेश पाने में सफल नहीं रही है। पर साठ वर्षों से स्थापित परिपाटी को तोड़ते हुए भाजपा- एनडीए गठबंधन की सरकार जनता का विश्वास मत पाने में सफल रही।

यह जनादेश बीजेपी-एनडीए गठबंधन के लिए ऐतिहासिक विजय है। साठ वर्षों से चली आ रही परिपाटी के अनुसार 2024 का चुनाव विपक्ष के लिए एक सुनहरा अवसर था। क्योंकि किसी सरकार का लगातार तीसरी बार सरकार में आना लोकतंत्र में बहुत ही कठिन कार्य होता है। फिर भी विपक्ष नाकामयाब क्यों रहा? विपक्ष लगातार तीसरे चुनाव में भी जनता का भरोसा क्यों नहीं जीत पाया? 13 राज्यों में तो विपक्ष अपना खाता खोलने में भी नाकामयाब क्यों रहा? कैसे कांग्रेस का कई राज्यों से सफाया कोई नई बात नहीं है। “इंडिया इज इंदिरा-इंदिरा इज इंडिया” के बाद भी सन् 1977 के आम चुनाव में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली व हरियाणा में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई थी, मध्यप्रदेश व राजस्थान में केवल एक-एक सीट से संतोष करना पड़ा था। स्वयं इंदिरा गांधी व राजपुत्र को भी लोकसभा के लिए सीट नहीं मिल पाई थी। स्पष्ट है विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में सफल नहीं हो पाया। सवाल यह नहीं है कि भूमिका निभाने में सफल नहीं हो पाया? या इससे भी महत्वपूर्ण सवाल है-विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाने का कोई प्रयास ही नहीं किया। बीते 10 वर्षों में ना तो सदन में विपक्ष ने कोई रचनात्मक प्रयास किया, ना ही जनता के बीच। विपक्ष का आभाव या विपक्ष का जिम्मेदारी से विमुख होना

लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। विपक्ष का झूठ के कारोबार से जनता की अदालत में टिकना संभव नहीं है, जनता में भ्रम फैला कर तत्काल तो सनसनी पैदा की जा सकती है, जनता का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है या समाचार पत्रों में स्थान पाया जा सकता है। पर आरोप लगाने वाले नेताओं की छवि बनाना की जगह बिगड़ और जाती है। जिस तरह जिस आत्मविश्वास के साथ 2019 के चुनाव में विपक्ष के नेताओं ने सरकार व प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाए थे, वही नेता फिर कोर्ट में हाथ जोड़कर, बिना शर्त माफी मांग कर, स्वयं अपने आरोपों को झूठ का पुलिंदा, भ्रामक जानकारी व तथ्यों को आधारहीन स्वीकार कर कोर्ट से छुपते-छुपाते हुए वापस आए। उससे विपक्ष के नेताओं की जनता के बीच में छवि बनना तो दूर, मिट्टी में और मिल गई या कालिख पुत गई। विपक्ष चमत्कार, जातिवाद, तुष्टिकरण व ध्रुवीकरण के सहारे सरकार में आना चाहता है। कुछ हद तक कभी-कभी छोटी-छोटी सफलता भी हासिल हो जाती है पर सफलता का आधार-आधारहीन होने के कारण आई हुई सफलता भी हाथ से चली जाती है। मतदाताओं के विवेक, ज्ञान व अनुभव को नकारा करना महंगा पड़ जाता है। मतदाता जागरूक हो चुका है। वह मताधिकार का प्रयोग विश्लेषण के उपरांत करता है भूतकाल, वर्तमानकाल व भविष्य को देख कर करता है। और जिस राजनीतिक दल को मत प्राप्त होता है, वह मत राजनीतिक दल के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होती है।

कांग्रेस के पास विरासत है। कई वर्षों तक देश पर राज संभाला है वह भी लगभग एक ही परिवार ने। पर दुर्भाग्य से विरासत के आधार पर वोट मांगने पर, वोट की जगह कांग्रेस के प्रति नकारात्मकता और फैल जाती है। अनेक वर्षों का शासन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पर फिर दुर्भाग्य सामने आकर खड़ा हो जाता है। इन अनेक वर्षों के शासन के आधार पर वोट मांगने की स्थिति भी नहीं बनती। बीजेपी-एनडीए गठबंधन के 10 वर्षों के बेदाग व शानदार शासन की उपलब्धियों के सामने कांग्रेस के शासन की

बातचीत चर्चा में लाना भी महंगा पड़ जाता है, महंगा ही नहीं बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है। मतदाताओं के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन करने पर भाजपा का 10 वर्षों का शासन कांग्रेस के लिए शासन के ऊपर भारी ही नहीं बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है। अब कांग्रेस के पास शेष केवल झूठ, नकारात्मकता, तुष्टिकरण, वोटों का ध्रुवीकरण, परिवारवाद, जातिवाद व भ्रष्टाचार को संरक्षण ही रह जाता है। इन हथियारों के सहयोग से थोड़ी बहुत सफलता मिल भी जाती है, पर अब मतदाता बहुत जागरूक हो गया है धीरे-धीरे यह हथियार रूपी हथकंडे भी निष्प्रभावी होते जा रहे हैं।

अब अगर बीजेपी-एनडीए गठबंधन की तरफ नजर डालें तो भाजपा की विरासत प्रेरणादायी, राष्ट्रीयता से भरी हुई, संविधान व लोकतंत्र के प्रति पूर्ण समर्पण, देशहित सर्वोपरि के साथ वसुधैव कुटुम्बकम्, भ्रष्टाचार के खिलाफ शंखनाद, परिवारवाद से मुक्ति, तुष्टिकरण नहीं संतुष्टिकरण, तुष्टिकरण से कोई समझौता नहीं के साथ-साथ महिला सम्मान-मातृ शक्ति के रूप में, 10 वर्षों की उपलब्धियों से भरा हुआ शासन, 5वीं अर्थव्यवस्था, 2027 तक तीसरी अर्थव्यवस्था की गारंटी, 2047 तक विकसित भारत का निर्माण, विश्व में भारतीय होने का गर्व, 15 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित भाजपा के प्रधानमंत्री, जिन पर विपक्ष भी आज तक एक भी आरोप नहीं लगा पाया, इतना संतुलन, समर्पण और त्याग के साथ-साथ कठोर तप ही सफलता के रास्ते का निर्माण करता है।

भाजपा की विरासत और भाजपा के 10 वर्षों का शासन ही संगठन के लिए भविष्य का रास्ता निर्धारित करता है व प्रेरणा प्रदान करता है। मतदाताओं का पूरा भरोसा ही संगठन व सरकार की महान उपलब्धि है। ■

(संजय गोविन्द खोचे)

सम्पादक



# 2024 चुनाव-सफल रही भाजपा की रणनीति

2024 का लोकसभा चुनाव अपने आप में एक बेहद रोचक तथा विशिष्ट चुनाव है। देश के मतदाताओं को केवल एक सरकार चुनने का चुनाव नहीं करना था। तीसरी बार देश की बागडोर भाजपा के हाथों में देना है या नहीं देना- इस बात का निर्णय करना था। निर्णय बेहद गंभीर व कठिन था पर देश ने, जनता ने जिस सहजता से निर्णय लिया, जितनी आसानी से निर्णय लिया-यह देश में लोकतंत्र की मजबूती, मतदाताओं के परिपक्वता, देश की इच्छा शक्ति को दिखाता है। 60 वर्षों के उपरांत मौका आया जब मतदाताओं ने किसी सरकार को तीसरी बार लगातार कार्य करने का जनादेश दिया है। लगातार तीसरी बार का जनादेश- इस बात का सबूत है जनता का अपने नेता, भाजपा-एनडीए गठबंधन पर पूरा भरोसा बरकरार है या बीजेपी-एनडीए गठबंधन की सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में जनता में कोई निराशा का भाव नहीं आया। सरकार के कामकाज के प्रति जनता का उत्साह व विश्वास बरकरार है यह सरकार व भाजपा-एनडीए गठबंधन के लिए जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है तथा भाजपा-एनडीए गठबंधन की बहुत बड़ी राजनैतिक सफलता है। सफलता शब्द बहुत छोटा व आसान शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ भी बहुत सरल है, पर सफलता हासिल करना तप है, विराट सफलता-विराट तप का परिणाम है, धैर्य की पराकाष्ठा का परिणाम है, जनता की आशाओं-अपेक्षाओं को केंद्र में रखकर रात-दिन एक करके लक्ष्य के प्रति समर्पण का परिणाम है। सफलता के पीछे के तप की वास्तविक परिकल्पना भी असंभव है, सफलता अचानक नहीं मिल जाती है। पीढ़ियों की तपस्या व लक्ष्य बनाकर पीढ़ी दर पीढ़ी किये गए तप से जनता के विश्वास का आशीर्वाद हासिल होता है।

संगठन व संगठन की ताकत के पीछे जाने कितने असंख्य कार्यकर्ताओं के न्योछावर शामिल हैं, जिनके लिए सत्ता तो बहुत दूर की कौड़ी थी, कल्पना से भी परे थी पर उद्देश्य-लक्ष्य प्राप्ति की ज्वाला को जीवित रखने के लिए, स्वयं को समिधा बनाने के लिए, वीरों के भाँति सतत संघर्ष जारी रहा। भाजपा का विराट



भाजपा कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बन सकता है पर उसका रिमोट किसी और के हाथ में नहीं होता। वह किसी व्यक्ति विशेष के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। वह संसद और देश की जनता के प्रति उत्तरदायी होता है।

उसका अपना परिवार शासन या संगठन पर हावी नहीं होता है। देश के 140 करोड़ लोग बिना भेदभाव के-चाहे बीजेपी को वोट दें या बीजेपी से नफरत करें, भाजपा के प्रधानमंत्री के परिजन होते हैं, भाजपा के प्रधानमंत्री का परिवार विशाल, विराट होता है, विविधताओं से भरा 140 करोड़ लोगों का होता है।

संगठन- वह आज एनडीए गठबंधन के साथ 20 प्रदेशों में एनडीए सरकार का मुख्यमंत्री-अपने आप में बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है। आखिर यह राजनीति है क्या? जो भाजपा को अन्य दलों या मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से अंतर पैदा करती है? याद रखिए जनसंघ जो अब भाजपा है की उत्पत्ति स्वतंत्र भारत

के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से वैचारिक मतभेदों के चलते हुई थी। इस संगठन के नींव वैचारिक है, जिसमें देश भक्ति है, देश के नागरिकों के अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता, विरासत और संस्कृति की रक्षा, महिलाओं, बुजुर्गों, पर्यावरण, जीव-जंतुओं की रक्षा का वचन है। परिवारवाद का हर स्तर पर विरोध है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ शंखनाद है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं- भारत माता है, जिसके वैभव, सीमाओं की रक्षा, सुरक्षा के साथ-साथ भारत को आधुनिक भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना जैसे तमाम मुद्दे शामिल हैं। आज पूरा विश्व मानने लगा है कि भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना ही पड़ेगा। भारत के विकास में ही विश्व का कल्याण है। भारत के प्रधानमंत्री के विचारों में, विरासत में “वसुधैव कुटुंबकम्” है और भाजपा सरकार भारत के गौरवशाली परंपरा व संस्कृति की रक्षा के लिए वचनबद्ध है और पिछले 23 (13 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में एवं 10 वर्ष प्रधानमंत्री के रूप में) वर्षों के शासन में ऐसा कोई भी उदाहरण पेश नहीं आया जो भाजपा की कथनी से भिन्न हो, जनता का भरोसा क्षणिक आवेश में आया निर्णय नहीं- लंबी तपस्या का परिणाम है। भाजपा ही वह संगठन है जिसमें देश का कोई भी नागरिक पार्टी का विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के साथ-साथ भाजपा अध्यक्ष या महत्वपूर्ण पदाधिकारी बनकर क्षेत्र-प्रदेश-देश-विश्व का नेतृत्व कर सकता है। कोई सीट किसी व्यक्ति, परिवार के लिए रिजर्व नहीं है।

भाजपा कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बन सकता है पर उसका रिमोट किसी और के हाथ में नहीं होता। वह किसी व्यक्ति विशेष के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। वह संसद और देश की जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। उसका अपना परिवार शासन या संगठन पर हावी नहीं होता है। देश के 140 करोड़ लोग बिना भेदभाव के- चाहे बीजेपी को वोट दें या बीजेपी से नफरत करें, भाजपा के प्रधानमंत्री के परिजन होते

हैं, भाजपा के प्रधानमंत्री का परिवार विशाल, विराट होता है, विविधताओं से भरा 140 करोड़ लोगों का होता है। फिर प्रधानमंत्री जी किसी व्यक्ति विशेष से राग, अनुराग या द्वेष कैसे रख सकते हैं, तभी भाजपा सरकार का हर निर्णय देश के लिए होता है। “भारत प्रथम” की नीति पर होता है। 140 करोड़ लोगों के लिए होता है। किसी क्षेत्र विशेष या किसी धर्म विशेष को लाभ पहुंचाने के दृष्टि से नहीं लिया जाता। भाजपा के प्रधानमंत्री का परिवार देश में रह रहे 140 करोड़ लोगों तक की सीमित नहीं होता है, इस पृथ्वी पर किसी भी कोने में रह रहा हर भारतवंशी भाजपा के प्रधानमंत्री के परिवार का सदस्य होता है। विदेशों में रह रहे भारतवंशियों को बहुत मजबूत व ठोस भरोसा है- भारत में भारत माता का सपूत भारत का प्रधानमंत्री है यह भरोसा है, विश्वास है, यह भरोसा ही विदेशों में रह रहे भारतवंशीयों का आत्मविश्वास है, यह भरोसा ही वह अदृश्य शक्ति है जिसके भरोसे भारतवंशियों का मस्तक विदेशों में भी गर्व से भरा रहता है उन्हें भारतवंशी होने का अभिमान दिलाता है। उन्हें भरोसा है उनके पास 140 करोड़ लोगों का नेता उनके साथ है। चाहे दूरियां कितनी भी हों पर दिल से दिल की वास्तविक दूरी शून्य है। यह भरोसा शब्दों के समायोजन से नहीं बनता, हर आपदा में भारत का प्रधानमंत्री, हर भारतवंशी के साथ हर पल खड़ा मिला है, चाहे कोरोना काल हो, चाहे यूक्रेन युद्ध हो, या किसी भी तरीके की कोई भी अन्य आपदा हो। सोचिए जिस प्रधानमंत्री का विदेशों में रह रहे भारतवंशियों को इतना भरोसा है तो भारत में रह रहे भारतीयों को कितना बड़ा भरोसा होगा। पड़ोसी देशों में रह रहे भारतवंशी, जो उन देशों में

अल्पसंख्यक हैं और उन देशों के अल्पसंख्यक होने के साथ-साथ अमानवीय अत्याचारों को सहते हैं, उनको भी सम्मान के साथ भारत में रहने का अधिकार प्रदान किया गया। नागरिकता प्रदान करने का रास्ता निकाला गया। यही नहीं प्रधानमंत्री जी “वसुधैव कुटुंबकम्” का पालन करते हैं। पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं तभी तो कोरोना काल में 100 से अधिक देशों को मुफ्त वैक्सीन की सप्लाई करते हैं। यही तो भारत के प्रधानमंत्री में विशेषता है जो भाजपा को अन्य दलों से अलग खड़ा करती है यह विशेषताएं ही भाजपा की रणनीति का हिस्सा हैं, यह विशेषताएं ही भाजपा संगठन का सिद्धांत हैं, यह विशेषताएं ही भाजपा की पहचान हैं।

2014 के आम चुनाव से पहले- 2004 से 2014 तक, लगातार 10 वर्षों तक-विश्व के सर्वाधिक योग्य माने जाने वाले अर्थशास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, पर उनके शासनकाल में अंधेरा क्यों छाया रहा? निराशा चरम तक क्यों पहुंच गई? देश 9वीं अर्थव्यवस्था से 11वीं अर्थव्यवस्था तक क्यों पहुंच गया? आतंकवाद क्यों हावी हो गया था? सीमाओं की सुरक्षा करने में सरकार क्यों नाकामयाब थी? सेना पर पत्थर क्यों फेंके जाते थे? सेना के हाथ क्यों बांध के रखे गए थे? मंत्रियों तथा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप सामान्य चर्चा का विषय क्यों बन गये थे? नभ-जल-थल हर जगह भ्रष्टाचार क्यों चरम पर था? भारत जैसे विशाल देश का प्रधानमंत्री असहाय क्यों था? क्या प्रधानमंत्री का देश के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं था? या देश के नागरिकों के प्रति कोई कर्तव्य शेष नहीं था? क्या युवाओं का भविष्य अंधकार में डालना कोई अपराध नहीं था? पर पूरे 10 वर्ष के शासनकाल पर नजर डालें तो 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री जी देश के जनता के प्रति उत्तरदायी होने की जगह- उनको प्रधानमंत्री बनाने वाली ताकतों के समक्ष समर्पण को महत्व देते रहे और उन ताकतों के हितों को देश से ऊपर रखा गया। प्रधानमंत्री जी के दो वाक्य भी 2004 से 2014 तक ऐसे सुनाई नहीं आ पाए जिसमें देश पहले दिखाई दिया हो। और ऐसा होता भी क्यों? राजमहल को खुश रखो- जनता की क्या बिसात।

**भाजपा की सफलता के पीछे रणनीति की सफलता है।**

किसी भी संगठन की सफलता या असफलता उसके नेतृत्व की क्षमताओं, आदर्शों, विचारों, आचरण और जनता के पूर्व के अनुभवों से अर्जित विश्वास के साथ होती है। यह चीज भाजपा की राजनीतिक सफलता का आधार है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से शुरू हुई इस यात्रा को समय-समय पर आए भाजपा नेतृत्व ने





नये आयामों के साथ और आगे बढ़ाया, विराट स्वरूप प्रदान किया गया। ऐसा नहीं है यह यात्रा शांति पूर्वक गुजरती चली गई, इस यात्रा में पग-पग पर कांटे बिछाए गए, यात्रा को दबाने, कुचलने यहाँ तक समाप्त करने तक का प्रयास किया गया। बलिदान भी मांगे गए, आपातकाल लगाकर जेलों में ठूँसा गया, आवाज पर ताला लगाया गया, यातनाओं का, प्रताड़नाओं का, निरंकुश शासन का एक दौर तो वो भी निकला है, जब जनसंघ का नाम लेना भी अपराध से कम ना था, डर तो इतना था कि रिश्तेदार, सगे-सम्बन्धी भी जनसंघियों से संबंधों को नकार देते थे। फिर भी यात्रा ना कभी समाप्त हुई, बल्कि बाधाओं, प्रताड़नाओं की छांव में और जोश से, और शक्ति के साथ आगे आई, क्योंकि यह यात्रा व्यक्तिगत स्वार्थों, या व्यक्तिगत उद्देश्यों से परे थी, यह यात्रा वैचारिक थी, देश के कोने-कोने से लोग जनसंघ के संगठन से जुड़ने लगे, केवल हिंदी भाषी राज्यों की पार्टी कहलाई जाने वाली पार्टी 303 लोकसभा सदस्यों को अपने झण्डे के नीचे खड़ा करने वाली पार्टी भी बन चुकी है, 303 लोकसभा सदस्यों का विशाल जन समर्थन, किसी नेता की हत्या से उपजा सहानुभूति वोट नहीं, जनता के भरोसे से प्राप्त वोट से संभव हुआ है। जो स्थाई होता है। गैर कांग्रेसी सरकार का 10 वर्षों के शासन के बाद भी 240 लोकसभा सदस्यों के साथ वापस आना आसान बात नहीं असम्भव बात है।

2024 का चुनाव जनता के भरोसे के वोट का चुनाव है। नेतृत्व के रिकॉर्ड पर जनता के निर्णय का चुनाव है। रीति-नीति पर भरोसे का चुनाव है। ईमानदारी पर जनता की जोरदार व मजबूत गवाही है। उज्ज्वल भविष्य के लिए कमान सौंपने का भरोसा है। विश्व शांति के लिए शक्तिशाली भारत के निर्माण का जनादेश है। आत्मनिर्भर भारत को चुनने का जनादेश है। संविधान के प्राणों की रक्षा के लिए योग्य पहरेदार को चुनने का जनादेश है, देश की आधी जनसंख्या या देश की आधी शक्ति या देश की मातृशक्ति को देश की निर्णयों में शामिल करने का जनादेश है। गरीबी रेखा से देश की नागरिकों को ऊपर लाने वाली सरकार के लिए जनादेश है। सीमा- सैनिक का सम्मान व सुरक्षा के रणनीति के सम्मान का जनादेश है। कोई नागरिक बीमारी में अकेला नहीं रहेगा इलाज की व्यवस्था करने वालों का चुनाव है। टैक्सों के मकड़जाल से पैसों की उगाही के रोक का जनादेश है। भ्रष्टाचार पर प्रहार के लिए जनादेश है। तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने वाली सरकार का जनादेश है। दिल्ली से चलने वाले रूपये को सीधे हितग्राहियों के खाते में भेजने वाली सरकार का जनादेश है। तीन तलाक की तलवार

को दफन करने वाली सरकार का जनादेश है। आतंकवाद, नक्सलवाद को समाप्त करने वाली सरकार का जनादेश है। निर्णय लेने वाली सरकार का जनादेश है। 56 इंच के सीने वाली सरकार का जनादेश है।

2024 के चुनाव का समग्र चिंतन किया जाए तो जनादेश भाजपा के 13 वर्षों एवं 10 वर्षों के शासनकाल, नीतियों, उद्देश्यों, विचारों, आशाओं-अपेक्षाओं, नेतृत्व के प्रति भरोसा और रणनीति की सफलता का जनादेश है। यही रणनीति है जो भारतीय जनता पार्टी को और दलों से अलग खड़ा करती है, अंतर बनाती है, भाजपा के शासनकाल में न केवल भारत

सुरक्षित है, बल्कि विश्व भी शांति के लिए भाजपा के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की बड़ी भूमिका का आकांक्षी है।

आज विश्व शांति के लिए सभी पक्ष भारत से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। उन्हें मालूम है आज भारत युवा देश है जिसके प्रधानमंत्री विश्व को शांति के रास्ते पर ले जा सकते हैं। विश्व को भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का विकास भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए उपयोगी है। भाजपा इस भरोसे को जीतने में कामयाब रही है। यही भाजपा की सबसे बड़ी पूँजी है। ■

## रिकॉर्ड प्रचंड जीत डॉ. मोहन यादव



### प्रधानमंत्री

श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के कार्यों के साथ सत्ता और संगठन के समन्वय से लोकसभा के चुनाव में सभी 29 सीटों पर ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई है। इस चुनाव में हम छिंदवाड़ा लोकसभा भी जीते हैं और हमने 100 प्रतिशत नहीं, बल्कि 120 प्रतिशत परिणाम दिया है। सभी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव की इस जीत के हकदार हैं। इस चुनाव में भाजपा ने जो रिकॉर्ड बनाया है, वह भविष्य में कोई तोड़ नहीं सकता। भविष्य में कोई दल सभी 29 सीटें जीतता है तो वह हमारे रिकॉर्ड की सिर्फ बराबरी करेगा, तोड़ नहीं पाएगा। विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता संभालने के कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावी हो गई, विकास कार्यों को करने के लिए अधिक समय नहीं मिला था। अब आने वाले दिनों में प्रदेश के सभी विधायकों, जिला अध्यक्षों के साथ, प्रदेश संगठन के साथ मिलकर आगामी 4 वर्षों के विकास का रोडमैप बनाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश को विकास के नए आयाम तक पहुंचाने के लिए सत्ता और संगठन में समन्वय के माध्यम से तकनीक का उपयोग कर प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश के विकास को और गति देने के लिए औद्योगीकरण के लिए सुविचारित प्रयास किया जाएंगे। ■



# आपातकाल प्रजातंत्र का गला घोटने का कुत्सित प्रयास : जगत प्रकाश नड्डा

- आपातकाल को देश पर थोपने और प्रजातंत्र का गला घोटने का जो कुत्सित प्रयास हुआ था, उसे जनता के सामने लाने का भाजपा प्रयास कर रही है।
- आपातकाल के दौरान भारतीय जनसंघ के कई नेताओं को एक दिन या दो दिन नहीं, बल्कि 19 महीनों से ज्यादा जेल में रहना पड़ा था और इन नेताओं का कसूर सिर्फ इतना था कि ये प्रजातंत्र की रक्षा और मजबूती के लिए आवाज उठा रहे थे।
- कांग्रेस की सोच एवं उनकी कार्यशैली में प्रजातंत्र की कोई गुंजाइश ही नहीं है और जिसने इनका विरोध किया, उसे समाप्त करने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है।
- कांग्रेस ने 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है। 1973 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सबसे वरिष्ठ जज को दरकिनार कर जस्टिस अजीत नाथ रे को चीफ जस्टिस बनाया।
- प्रजातंत्र की दुहाई देने वाले राहुल गांधी ने 2013 में अपनी ही सरकार द्वारा संसद में पारित किए गए अध्यादेश की प्रति फाड़ने का काम किया था।
- 12 जून, 1975 को इलाहाबाद की हाई कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट ने अनुचित तरीके से चुनाव लड़ने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया गया था और उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी।

**25 जून** 1975 को देश के प्रजातंत्र के गले को घोटकर देश में

आपातकाल लगाया गया था और इसको जनता के समक्ष लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में काला दिवस के कार्यक्रम को आयोजित किया। आपातकाल के समय की कुर्नीति देश के लिए कितनी बड़ी चुनौती



आपातकाल के समय नारा लगा था 'इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया'। इस तरह के प्रजातंत्र का गला घोटने वाले ये लोग थे। यह बात अलग है कि राहुल गांधी इतिहास कम पढ़े हैं, इसलिए उनको इतिहास की जानकारी कम है और पता नहीं उनकी डिग्री कितनी है।

कांग्रेस की सोच एवं उनकी कार्यशैली में प्रजातंत्र की कोई गुंजाइश ही नहीं है और जिसने विरोध किया, उसे समाप्त करने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है।

है, यह जानना एक सजग प्रजातन्त्र के लिए अति आवश्यक है।

देश ने कुछ समय पहले ही लोकसभा चुनाव के महापर्व को मनाकर 18वीं लोकसभा का गठन किया है। भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है और यह प्रक्रिया लगभग 1100 वर्ष पुरानी है। उत्तरमेरु स्थान पर प्रजातन्त्र की बुनियादी बातों का जिक्र मिलता है। कांग्रेस ने ऐसे ऐतिहासिक प्रजातंत्र के गला घोटने का काम किया। देश एकजुट होकर आपातकाल के खिलाफ खड़ा हुआ और सबने डटकर इसका विरोध किया था, जिसका नतीजा है कि देश में प्रजातंत्र भी बहाल हुआ और देश ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया को पूर्ण किया है। युवा

आपातकाल को देखने वाले लोगों से मिलें और उनके अनुभवों को जानने का प्रयास करें। नौजवान कभी कल्पना भी नहीं कर सकता की उस समय जिन लोगों ने प्रजातंत्र की रक्षा के लिए अपनी आहुति दी थी उसकी ताकत के कारण प्रजातंत्र मजबूत होकर खड़ा है। देश में आपातकाल के दौरान दुख के दिनों के 50 वर्ष हो गए हैं। जनता कल्पना नहीं कर सकती एक रात में 9 हजार लोगों को जबरन उठा लिया गया जिसमें मोरारजी देसाई, मोहन धारिया, अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी जैसे नेताओं की लंबी श्रृंखला है, जिनको 25 जून 1975 को हिरासत में ले लिया गया और इन नेताओं को एक दिन या दो दिन नहीं, बल्कि 19 महीनों से ज्यादा जेल में रहना पड़ा था। इन नेताओं का कसूर सिर्फ



इतना था कि इन्होंने प्रजातंत्र की रक्षा और मजबूती के लिए आवाज उठाई थी।

12 जून, 1975 को इलाहाबाद की हाई कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट ने अनुचित तरीके से चुनाव लड़ने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया गया था और उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद संविधान को बदलकर इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी को बचाने का प्रयास किया। जिसके बाद पूरा देश उद्वेलित हो गया और इस उद्वेलना को रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने 25 जून, 1975 की रात को आपातकाल की घोषणा की और हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। देश की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने उस समय अपना योगदान दिया था। लगभग 1 लाख 40 हजार लोग आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (MISA) और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स (DIR) के तहत लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें से लगभग 75 से 80 हजार लोग भारतीय स्वयंसेवक के लोग थे। ऐसे लाखों परिवारों ने देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ लगाकर देश की रक्षा के लिए आये थे।

आपातकाल के समय इस तरीके का वातावरण बना दिया था की घर के अंदर भी उन्मुक्तता से बात नहीं कर सकते थे और उस समय कॉलेज पुलिस की छावनी लगती थी। इंटरमीडिएट के दौरान कई विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया था वो भी सिर्फ इंकलाब जिन्दाबाद के नारे के कारण। उस समय इतने लोगों को गिरफ्तार कर रहे थे लेकिन एक का भी मनोबल नहीं टूटा और हर दिन सत्याग्रह हो रहे थे।

आपातकाल के समय नारा लगा था 'इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया'। इस तरह के प्रजातंत्र का गला घोटने वाले ये लोग थे। यह बात अलग है कि राहुल गांधी इतिहास कम पढ़े हैं, इसलिए उनको इतिहास की जानकारी कम है और पता नहीं उनकी डिग्री कितनी है। कांग्रेस की सोच एवं उनकी कार्यशैली में प्रजातंत्र की कोई गुंजाइश ही नहीं है और जिसने विरोध किया, उसे समाप्त करने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें जो कांग्रेस दल के चयनित अध्यक्ष थे, लेकिन उन्हें पार्टी के दबाव में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा।

सबसे लोकप्रिय नेता सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, कांग्रेस ने हमेशा संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ अपना

उम्मीदवार खड़ा किया और जब भी वे चुनाव लड़े, उनका विरोध किया। यह भी सच है कि बाबा साहब अंबेडकर को कैबिनेट का सदस्य होने के बाद भी इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस पार्टी की सोच में विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है। अगर कोई विरोध करता है तो कांग्रेस उसे खत्म कर देती है। मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों के तहत कई पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। कांग्रेस के नेता संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं, लेकिन उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है। उन्हें राजघाट जाकर देश की जनता से आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने के अपने कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए।

विपक्ष प्रजातंत्र की दुहाई देकर संविधान की रक्षा की बातें कर रहा है। जबकि कांग्रेस ने 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है।

1973 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने चीफ जस्टिस के पद पर सबसे वरिष्ठ जज को दरकिनार कर जस्टिस अजीत नाथ रे को चीफ जस्टिस बनाया। कांग्रेस सरकार ने जस्टिस खन्ना को दरकिनार कर जस्टिस बेग को भी देश का चीफ जस्टिस नियुक्त किया था। धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाली कांग्रेस ने सूडो-सेक्युलरिज्म का उदाहरण प्रस्तुत किया है। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानों मामले में निर्वाह निधि देने का निर्णय किया था, मगर 21वीं सदी की ओर देखने वाले राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन करके इस निर्णय को पलटने का कार्य किया था। विपक्ष आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की भावना के खिलाफ खड़ा है।

कांग्रेस सरकार ने शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत आस्था के साथ भेदभाव किया, जहां अल्पसंख्यक संस्थानों को सभी तरह की सुविधाएं और रियायतें प्रदान की गईं लेकिन बहुसंख्यक संस्थानों के साथ दोहरा मापदंड अपनाया गया।

प्रजातंत्र की दुहाई देने वाले राहुल गांधी ने 2013 में अपनी ही सरकार द्वारा संसद में पारित किए गए अध्यादेश की प्रति फाड़ने का काम किया था। जनता ने विपक्ष को आईना दिखा दिया, मगर रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। विपक्ष अपनी चर्चाओं में संसदीय मर्यादाओं और शब्दावली का ध्यान नहीं रखता है।

देश में कभी भी लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसी शर्त के साथ नहीं हुआ, मगर विपक्ष ने कहा कि पहले लोकसभा उपाध्यक्ष



का पद तय करें, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष पर समर्थन दिया जाएगा। यह मांग कांग्रेस कर रही है, जिसने तेलंगाना और कर्नाटक में सरकार बनने के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही पद अपने पास रखे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी, तमिलनाडु में डीएमके और केरल में सीपीआई का ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। विपक्ष के लोग दोहरे मापदंड में जी रहे हैं और जनता को इनकी मानसिकता के बारे में पता चल चुका है।

आपातकाल को याद करते हुए समझना होगा कि कांग्रेस के मन में यही विचार है कि इनकी मानो नहीं, तो ये जनता के साथ मनमर्जी व्यवहार करेंगे। आपातकाल के समय कांग्रेस ने षड्यन्त्र कर प्रजातंत्र का गला घोटने का प्रयास किया। कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय जैसे संस्थान को अपनी गिरफ्त में लेने का कार्य किया था और आज कांग्रेस देश के संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की बातें कर रही है।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों तक सरकार चली, लेकिन जम्मू-कश्मीर को छोड़ किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया और जम्मू-कश्मीर में भी जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। प्रजातंत्र के मूल्यों के लिए जीना पड़ता है। बिहार में लालू सरकार ने उपद्रव किया था और आज पश्चिम बंगाल में प्रजातंत्र का गला घोंटा जा रहा है और घुसपैठियों को पनाह दी जा रही है। भाजपा प्रजातंत्र की लड़ाई प्रजातंत्र की ताकत से ही लड़ती है, लेकिन यह विपक्ष के लोग हर तरह से षड्यन्त्र कर प्रजातंत्र का गला घोटने का कार्य कर रहे हैं। ■



# आपातकाल "काला दिवस" अमित शाह



- एक परिवार की सत्ता के लिए कांग्रेस ने बार-बार संविधान की आत्मा को कुचला
- राजीव गांधी ने किया था इमरजेंसी का समर्थन, सदन में कहा था कि 'इसमें कुछ भी गलत नहीं'
- 'जरूरत होने पर इमरजेंसी न लगाए ऐसा नेता पीएम के लायक नहीं', अपने पिता का यह बयान भूल गए हैं कांग्रेस के युवराज
- आपातकाल के अत्याचारों पर गर्व करना यह दर्शाता है कि कांग्रेस के लिए एक परिवार और सत्ता सबसे महत्वपूर्ण हैं

**कांग्रेस** ने एक खास परिवार को सत्ता में बनाए रखने के लिए कई बार भारत के संविधान की भावना को कुचला है। कांग्रेस सरकार की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाकर लाखों लोगों पर निर्भम अत्याचार किए। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद आपातकाल को जायज ठहराया था।

देश में लोकतंत्र की हत्या और उस पर बार-बार आघात करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है। 25 जून 1975 को कांग्रेस की सरकार द्वारा देश में आपातकाल लगाया गया था, यह

राजीव गांधी द्वारा तानाशाही कृत्य पर गर्व करना दर्शाता है कि कांग्रेस को परिवार और सत्ता के अलावा कुछ भी प्रिय नहीं है। अहंकार में डूबी निरंकुश तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक परिवार की सत्ता के लिए कई महीनों तक देश में आपातकाल लगाए रखा था।

आपातकाल के दौरान नागरिकों के सभी प्रकार के अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, मीडिया पर सेंसरशिप लगा दिया गया था, संविधान में बदलाव किए गए और न्यायालय तक के हाथों को बांध दिया गया था।

लोकतंत्र कुचलने का सबसे बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी के युवराज यह भूल गए हैं कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने की कोशिश में देश पर आपातकाल थोपा था। कांग्रेस के युवराज के पिता राजीव गांधी ने 23 जुलाई 1985 को इस भयावह घटना पर गर्व करते हुए लोकसभा में कहा था कि आपातकाल में कुछ भी गलत नहीं है।

आपातकाल को लोकतंत्र के लिए घातक बताने के बदले राजीव गांधी ने यहां तक कहा था कि अगर इस देश का कोई प्रधानमंत्री इन परिस्थितियों में आपातकाल को जरूरी समझता है और आपातकाल को लागू नहीं करता है, तो वह इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है।

राजीव गांधी द्वारा तानाशाही कृत्य पर गर्व

करना दर्शाता है कि कांग्रेस को परिवार और सत्ता के अलावा कुछ भी प्रिय नहीं है। अहंकार में डूबी निरंकुश तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक परिवार की सत्ता के लिए कई महीनों तक देश में आपातकाल लगाए रखा था।

आपातकाल के दौरान नागरिकों के सभी प्रकार के अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, मीडिया पर सेंसरशिप लगा दिया गया था, संविधान में बदलाव किए गए और न्यायालय तक के हाथों को बांध दिया गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक समय था। आपातकाल के खिलाफ संसद से सड़क तक आंदोलन करने वाले असंख्य सत्याग्रहियों, समाजसेवियों, श्रमिकों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के संघर्ष को नमन्।



# आपातकाल-भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय



डॉ. मोहन यादव

**भारतीय** लोकतंत्र के इतिहास में 25 जून 1975 को लागू किया आपातकाल एक काले अध्याय के रूप में जुड़ गया है। इस दिन भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल के प्रावधानों के तहत हजारों विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। भारतीय लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी आपातकाल के कलंक से कभी मुक्त नहीं हो सकती।

कांग्रेस शासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के कारण देश की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने का बहाना बनाते हुए इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल लगाया था। इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि के लिए हर छह महीने में आपातकाल लगाने के लिए कहा था। आपातकाल के दौरान,

**आपातकाल को अक्सर स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक काला दौर माना जाता है। इस अवधि में बेलगाम सरकारी कैद, असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता पर सरकारी दमन की घटनाएं हुईं।**

मानवाधिकारों के लगातार उल्लंघन और प्रेस पर दमनकारी हद तक सेंसरशिप की खबरें आती रहीं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन को पर्यवेक्षकों और संवैधानिक विशेषज्ञों द्वारा चिंता के साथ याद किया जाता है।

इंदिरा गांधी ने खुद को सर्व शक्तिमान के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने पार्टी के कुछ करीबी सदस्यों और अपने छोटे बेटे संजय गांधी के परामर्श से कई सारे निर्णय लिए जिसका भारत के सामाजिक तानेबाने पर दूरगामी प्रभाव पड़ा।

आपातकाल को अक्सर स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक काला दौर माना जाता है। इस अवधि में बेलगाम सरकारी कैद, असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता पर सरकारी दमन की घटनाएं हुईं। मानवाधिकारों के लगातार

उल्लंघन और प्रेस पर दमनकारी हद तक सेंसरशिप की खबरें आती रहीं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन को पर्यवेक्षकों और संवैधानिक विशेषज्ञों द्वारा चिंता के साथ याद किया जाता है। दरअसल आपातकाल की बुनियाद 1967 के गोलकनाथ मामले से ही पड़ गई थी। गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि परिवर्तन मौलिक अधिकारों जैसे बुनियादी मुद्दों को प्रभावित करते हैं तो संसद द्वारा संविधान में संशोधन नहीं



किया जा सकता है। इसके बाद इस निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए, सरकार ने 1971 में 24वाँ संशोधन पारित किया। सर्वोच्च न्यायालय में सरकार द्वारा तत्कालीन राजकुमारों को दिए गए प्रिवीपर्स के मामले में भी इंदिरा गांधी की किरकिरी हुई थी। न्यायपालिका-कार्यपालिका की यह लड़ाई ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में जारी रही, जहां 24वें संशोधन पर सवाल उठाया गया था। 7-6 के मामूली बहुमत के साथ, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने संसद की संशोधन शक्ति को यह कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया कि इसका उपयोग संविधान के “मूल ढांचे” को बदलने के लिए नहीं किया जा सकता है। इंदिरा गांधी को यह नागवार लगा और उन्होंने केशवानंद भारती मामले में अल्पमत में शामिल लोगों में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश ए. एन. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया।

न्यायपालिका को नियंत्रित करने की इंदिरा गांधी की प्रवृत्ति की प्रेस और जयप्रकाश नारायण (जेपी) जैसे राजनीतिक विरोधियों ने कड़ी आलोचना की। जयप्रकाश नारायण ने देश में घूम-घूम कर इंदिरा सरकार के खिलाफ रैलियां की और कुछ राज्यों में छात्रों ने आंदोलन भी किये। इस बीच, सार्वजनिक नेताओं पर हत्या के प्रयास हुए और साथ ही तत्कालीन केन्द्रीय रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की बम से हत्या कर दी गई। इन सभी बातों से पूरे देश में कानून और व्यवस्था की समस्या बढ़ने का संकेत मिलने लगा, जिसके बारे में इंदिरा गांधी के सलाहकारों ने उन्हें महीनों तक चेतावनी दी थी। इसके बाद मामले को हाथ से निकलता देख इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाने का फैसला किया। कांग्रेस पार्टी का यह फैसला देश की लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध हुआ और इसे एक काला दिन के रूप में याद किया जाने लगा।

18 वीं लोकसभा के पहले दिन प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया और आपातकाल की घोषणा को भारत के लोकतंत्र पर एक “काला धब्बा” बताया। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा, “कल 25 जून है। 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर लगे उस कलंक के 50 साल हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह से नकार दिया गया था, संविधान के हर हिस्से की धजियां उड़ा दी गई थीं, देश को जेलखाना बना दिया गया और लोकतंत्र को पूरी तरह से दबा दिया गया था।” “उन्होंने कहा, अपने संविधान की रक्षा करते हुए, भारत

के लोकतंत्र की, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए, देशवासी यह संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कोई ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले किया गया था। हम एक जीवंत लोकतंत्र का संकल्प लेंगे। हम भारत के संविधान के निर्देशों के अनुसार आम लोगों के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेंगे।”

18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा होने के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रमुख मुद्दों में से एक संविधान बचाने का मुद्दा था। जिसे पार्टी आज भी जोर शोर से उठा रही है। विडंबना ये है कि जिस कांग्रेस ने संविधान में सैकड़ों संशोधन किए, उसके मूल ढांचे में संशोधन किए वह पार्टी आज संविधान बचाने की बात कर रही है। जिस भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति संविधान में दिए गए प्रावधान के तहत समाज के गरीबों, महिलाओं, वंचितों और दलितों की उत्थान के लिए है आज उस बीजेपी पर संविधान की दुर्दशा करने वाली कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। देश के महानायक प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कई बार इस बात का जिक्र किया है कि भारत की आत्मा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में बसती है और इसे संसद भी नहीं बदल सकता। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी द्वारा गलत अवधारणा फैला कर जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है। लोकसभा चुनावों में जनता कांग्रेस और उनके साथियों के झांसे में आ गई थी, लेकिन विपक्षी पार्टियों की काठ की यह हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। ■

(लेखक मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं)

## कानूनों में परिवर्तन ऐतिहासिक मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

### गुलामी

के प्रतीकों को समाप्त करने के क्रम में कुछ कानूनों में आमूलचूल परिवर्तनों का कार्य हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर देश में लागू पुलिस और न्याय व्यवस्था से जुड़े कई बदलाव किए जा रहे हैं। यह समाज के लिए सुव्यवस्थाएं स्थापित करने का प्रयास है। अच्छे और सकारात्मक भाव के साथ किए गए इन परिवर्तनों के लिए केंद्र सरकार बधाई की पात्र है।

काल के प्रवाह में अनेक विषय परिवर्तित स्वरूप में सामने आते हैं। भारत की प्राचीन न्याय पद्धति काफी सरल थी। हमारी पंच परम्परा भी अनूठी थी। राजा विक्रमादित्य की न्याय परम्परा से भी तत्कालीन समाज लाभान्वित था। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अंग्रेजों के शासन काल से लागू कानूनों में आवश्यक परिवर्तन का ऐतिहासिक कार्य किया है। मध्यप्रदेश में इन कानूनों को लागू करने के साथ ही उनके समुचित प्रचार प्रसार का कार्य भी किया जा रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने करीब चार सौ घंटे के परिश्रम और विभिन्न स्तर की बैठकों के बाद व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात नए कानूनों के प्रारूपों को अंतिम रूप प्रदान किया है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर सुझाव भी प्राप्त किए गए। पूर्व में भी नई शिक्षा नीति-2020 लागू करने के पहले करीब 2 लाख लोगों के सुझाव प्राप्त हुए थे। ■



# आपातकाल: अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक व अत्याचार का काल



तरुण चुघ

**भारत** संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विडंबना रही कि भारत को सदियों तक शासकीय प्रताड़ना झेलनी पड़ी। मुगलों के शासन में धार्मिक आधार पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता रहा है तो अंग्रेजों के शासन में शोषण के जरिए जनता प्रताड़ित होती रही। देश अंग्रेजी दासता से मुक्त हुआ तो यह उम्मीद जगी कि भारत अब प्रताड़ना के दंश से मुक्त हुआ। लेकिन, देश के आजाद होने के लगभग दो दशक बाद 1975 से 1977 तक जनता को ऐसी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जो प्रताड़ना की पराकाष्ठा थी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के इतिहास का वह एक काला अध्याय था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि में भारत प्रताड़ना की दौर में रहा। स्वतंत्र भारत के इतिहास का यह सबसे अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक एवं राजनीतिक अत्याचार का काल था। देश में सभी चुनाव स्थगित हो गए तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। मानवाधिकारों को कुचल दिया गया। तत्कालीन कांग्रेसी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया।

अभिव्यक्ति की आजादी समाप्त कर दी गई, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर उसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया। कोई भी समाचार पत्र सरकार की अनुमति के बिना कुछ भी प्रकाशित नहीं कर सकते थे। चार न्यूज एजेंसियों को एक कर उसे सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया था। लगभग चार हजार अखबारों को जब्त कर दिया गया तथा 327 पत्रकारों को मीसा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ढाई सौ अखबारों का विज्ञापन बंद कर दिया गया तथा सात विदेशी पत्रकारों को देश से निकाल दिया गया। दर्जन भर विदेशी पत्रकारों के भारत में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई तो कई को भारत से बाहर निकाल दिया गया। ऐसी अलोकतांत्रिक कार्यवाही करने वाली कांग्रेस पार्टी आज संविधान और अभिव्यक्ति की आजादी की बात करती है तो



**25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि में भारत प्रताड़ना की दौर में रहा। स्वतंत्र भारत के इतिहास का यह सबसे अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक एवं राजनीतिक अत्याचार का काल था।**

देश में सभी चुनाव स्थगित हो गए तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। मानवाधिकारों को कुचल दिया गया।

हास्यास्पद लगती है।

सरकार के अलोकतांत्रिक गतिविधियों का विरोध करने के लिए राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को प्रतिबंधित कर स्वयंसेवकों को यातनाएँ दी गईं। पुलिस इस संगठन पर क्रूरता के साथ टूट पड़ी थी। उसके हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। लाखों स्वयंसेवकों ने प्रतिबंध और मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन में भाग लिया।

कांग्रेस सरकार की तानाशाही ऐसी थी कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं और सरकार के आलोचकों के गिरफ्तार करने और सलाखों के

पीछे भेजने के बाद पूरा देश अर्चभित होने की स्थिति में आ गया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जननायक कर्पूरी ठाकुर समेत विपक्ष के तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।

आपातकाल की घोषणा के बाद पंजाब में विरोध मुखर हुआ। सिख नेतृत्व ने भी कांग्रेस के इस करतूत का विरोध किया। अमृतसर में बैठकों का आयोजन किया, जहाँ उन्होंने 'कांग्रेस की फासीवादी प्रवृत्ति' का विरोध करने का संकल्प किया। इस तरह देश के सभी राज्यों में केंद्र सरकार की तानाशाही के



खिलाफ आंदोलन मुखर होता गया। राज्य की विधानसभाओं से विपक्षी विधायकों ने इस्तीफा देना शुरू किया।

1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की जीत को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी गई चुनौती के बाद से देश में राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में माना कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया। इसलिए जन प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार उनका सांसद चुना जाना अवैध करार देकर छह साल तक उनके कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी के पास प्रधानमंत्री पद छोड़ने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अदालत ने कांग्रेस पार्टी को नया प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीन हफ्तों का समय दिया था। इस समय देश में 'इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया' का माहौल बना दिया गया था। ऐसे माहौल में इंदिरा के होते किसी और को प्रधानमंत्री कैसे बनाया जा सकता था? इंदिरा गांधी अपनी ही पार्टी में किसी पर भी विश्वास नहीं करती थीं। उन्होंने इस्तीफा देने के बजाय 3 हफ्तों की मिली मोहलत का फायदा उठाते हुए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर पूर्ण रोक लगाने से इंकार कर दिया। बिहार और गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ छात्रों का आन्दोलन उग्र हो रहा था। बिहार में इस आन्दोलन का नेतृत्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन यानी 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की रैली थी। उन्होंने इंदिरा गांधी पर देश में लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया और रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता के अंश 'सिंहासन खाली करो कि जनता आती है' का नारा बुलंद किया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने विद्यार्थियों, सैनिकों, और पुलिस वालों से अपील की कि वे लोग इस दमनकारी निरंकुश सरकार के आदेशों को ना मानें, क्योंकि कोर्ट ने इंदिरा को प्रधानमंत्री पद से हटने को बोल दिया है। महज इसी रैली के आधार पर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने का फैसला किया था। इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे देश में जन आक्रोश बढ़ रहा था। इसमें छात्र और सम्पूर्ण विपक्ष एकजुट हो गए थे।

इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने का सबसे बड़ा बहाना जयप्रकाश नारायण द्वारा बुलाया गया असहयोग आन्दोलन था। इसी आधार पर 26 जून 1975 की सुबह राष्ट्र के नाम अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा कि जिस तरह का माहौल देश में एक व्यक्ति अर्थात् जयप्रकाश नारायण द्वारा बनाया गया है, उसमें यह जरूरी

हो गया है कि देश में आपातकाल लगाया जाए। इसके साथ ही तत्कालीन भारतीय संविधान की धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी गई। आपातकाल लागू होने के साथ ही विरोध की लहर और तेज होती रही। अंततः प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर चुनाव कराने की सिफारिश कर दी। चुनाव में आपातकाल लागू करने का फैसला जनता को नागवार लगा। इस अत्याचार के विरोध की अगुवाई करने वाले लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने इसे 'भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि' कहा था।

1977 में हुए लोकसभा चुनाव में खुद इंदिरा गांधी अपने गढ़ रायबरेली से चुनाव हार गईं। जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। आजादी के 30 वर्षों के बाद केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। इस नई सरकार में जननेता अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश मंत्री के रूप में दुनिया के सामने भारत की जो तस्वीर पेश की, उसे आज भी लोग याद कर रहे हैं। अटलजी ने

पहली बार संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में अपना भाषण देकर दुनिया को भारत की भाषा की महत्ता समझाई। सूचना व प्रसारण मंत्री के रूप में लालकृष्ण आडवाणी ने सरकारी संचार माध्यमों को स्वायत्तता प्रदान कर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की।

देश में लगाए गए आपातकाल को भारत के राजनीतिक इतिहास की एक कलंक कथा के रूप में याद की जाती है। जेल में कैद के दौरान भारत रत्न अटलबिहारी वाजपेयी की कविताओं में उस समय की स्थिति का आकलन है:-

अनुशासन के नाम पर,  
अनुशासन का खून  
भंग कर दिया संघ को,  
कैसा चढ़ा जुनून  
कैसा चढ़ा जुनून, मातृपूजा  
प्रतिबंधित  
कुलटा करती केशव-कुल  
की कीर्ति कलंकित  
कह कैदी कविराय तोड़ कानूनी कारा  
गूंजेगा भारत माता की  
जय का नारा। ■  
(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं)

## आपातकाल भुलाया नहीं जा सकता : हितानंद जी



कांग्रेस समाज में भ्रम फैला रही है कि संविधान खतरे में है। जबकि संविधान को आपातकाल लागू करके कांग्रेस पार्टी ने ही खतरे में डाला था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी संविधान की रक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस ने 50 साल पहले आपातकाल लगाकर देश के लोकतंत्र और संविधान का किस तरह से गला घोटा था, आज की पीढ़ी को जानना आवश्यक है। वर्ष 1975 से 1977 के बीच देश की जनता ने जो भयावह दौर देखा उसे भुलाया नहीं जा सकता। आपातकाल के निरंकुश अत्याचारों ने देश की आत्मा को कभी न भरने वाले गहरे घाव दिये हैं। कांग्रेस की क्रूरता को सभी युवा जानें और उन लोगों को भी बताएं जिन्होंने आपातकाल में इनकी तानाशाही को नहीं देखा। ■



# भाजपा के कार्यकर्ता सजग प्रहरी विष्णुदत्त शर्मा



हम सभी ने मिलकर जीत का इतिहास बनाया है और आज पूरा मध्यप्रदेश भगवा रंग से आलोकित है। देश में फिर एनडीए की सरकार बनी है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर रिकॉर्ड बनाया है।

**लोकसभा** चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने देशभर में जो वातावरण बनाने का प्रयास किया, उसका प्रभाव मध्यप्रदेश में कहीं दिखाई नहीं दिया। इसका कारण यह था कि हर बूथ जीतने के संकल्प के साथ पार्टी का कार्यकर्ता एक सजग प्रहरी की तरह हर बूथ पर तैनात था। विधानसभा चुनाव में हमें 8 प्रतिशत अधिक वोट मिले थे और लोकसभा चुनाव में भी हमारा वोट प्रतिशत करीब 1.5 प्रतिशत बढ़ा है। हमने 75 से 80 प्रतिशत बूथों पर जीत हासिल करके इतिहास बनाया है। कार्यकर्ताओं ने प्रयास किए और पार्टी नेतृत्व ने

परिश्रम किया। सभी ने मिलकर अपनी-अपनी भूमिकाओं का निर्वाह किया और हम प्रदेश की सभी 29 सीटों जीतने में सफल हुए। हम सभी ने मिलकर जीत का इतिहास बनाया है और आज पूरा मध्यप्रदेश भगवा रंग से आलोकित है। देश में फिर एनडीए की सरकार बनी है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर रिकॉर्ड बनाया है। इस चुनाव में झूठ, छल-कपट, परिवारवाद, जातिवाद और विभाजन की राजनीति करने वाली ताकतें परास्त हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हार की नहीं, बल्कि अपनी जीत की भी समीक्षा करती है। ■

बूथ के  
कार्यकर्ता  
डटे रहे :  
सतीश उपाध्याय

पार्टी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से शानदार सफलता मिली है और पार्टी सभी 29 सीटों जीतने में सफल रही।

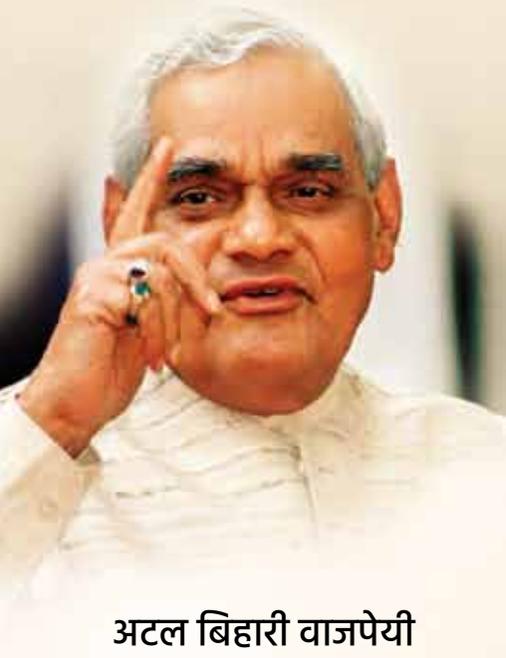
## समीक्षा हमारी कार्यपद्धति

का आधार है। भाजपा संगठन 100 में से 100 अंक हासिल करके भी अपने काम की समीक्षा करता है। क्या कमी रह गई और कैसे और अच्छा किया जाए, यही भाव भाजपा को अन्य दलों से अलग बनाता है। पार्टी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से शानदार सफलता मिली है और पार्टी सभी 29 सीटों जीतने में सफल रही। कार्यकर्ता प्रदेश के सभी 64523 बूथों पर सीमा प्रहरी की तरह डटे रहे और यही वजह रही उत्तरप्रदेश से सटे बुंदेलखंड अंचल में भी हम 100 प्रतिशत परिणाम हासिल करने में सफल रहे। इंडी गठबंधन के लोग जो भ्रम फैला रहे थे, हमारे कार्यकर्ताओं ने उसे मध्यप्रदेश में आने नहीं दिया।

हम सफलता के शीर्ष पर हैं और शीर्ष पर बने रहना बड़ी चुनौती है। लेकिन मध्यप्रदेश के पार्टी कार्यकर्ता इतने सक्षम हैं कि वो पार्टी को आने वाले समय में भी सफलता के शीर्ष पर बनाए रखेंगे और शानदार जीत हासिल करेंगे। ■



## जीवन की ढलने लगी साँझ



### अटल बिहारी वाजपेयी

जीवन की ढलने  
लगी साँझ  
उमर घट गई  
डगर कट गई  
जीवन की ढलने  
लगी साँझ।

बदले हैं अर्थ  
शब्द हुए व्यर्थ  
शांति बिना खुशियाँ हैं बाँझ।

सपनों से मीत  
बिखरा संगीत  
ठिठक रहे पाँव और झिझक  
रही झाँझ।  
जीवन की ढलने  
लगी साँझ।

## ऐतिहासिक विजय शिवप्रकाश जी

लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने देश भर में एक नैरेटिव सेट किया था, जिसको लेकर मध्यप्रदेश में भी विपक्ष ने भाजपा के खिलाफ खूब दुष्प्रचार किया कि 400 सीटें जीतने पर भाजपा संविधान बदल देगी, देशभर में आरक्षण समाप्त कर देगी। लेकिन यहां की जनता ने विपक्ष के मिथ्या आरोपों को पूरी तरह से नकार कर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाई है।

### मध्यप्रदेश का पार्टी संगठन

एक आदर्श संगठन है, इसे इस तरह से और मजबूत करें कि वह आगे भी आदर्श संगठन बना रहे। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए मध्यप्रदेश में जो प्रयास हुए हैं, वह बहुत अच्छे प्रयास हैं। सभी अच्छे प्रयासों की एक रिपोर्ट तैयार की जाए और पार्टी के प्रदेश संगठन को सौंपें, ताकि उस तरह के प्रयास आगे भी किए जा सकें। मध्यप्रदेश में लोकसभा की सभी 29 सीटों पर भाजपा ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है, यह केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन और प्रदेश के संगठन की मजबूती और सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही संभव हो सका है। लोकसभा चुनाव की समीक्षा के दौरान जो भी सुझाव आ रहे हैं, पार्टी

उन पर गंभीरता से विचार करेगी और उनको लेकर पार्टी को क्या करना है, उस पर भी कार्य किया जाएगा।

लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने देश भर में एक नैरेटिव सेट किया था, जिसको लेकर मध्यप्रदेश में भी विपक्ष ने भाजपा के खिलाफ खूब दुष्प्रचार किया कि 400 सीटें जीतने पर भाजपा संविधान बदल देगी, देशभर में आरक्षण समाप्त कर देगी। लेकिन यहां की जनता ने विपक्ष के मिथ्या आरोपों को पूरी तरह से नकार कर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाई है। लेकिन यह विषय अभी समाप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस, इंडी गठबंधन और अन्य विपक्षी



दल अभी भी भाजपा के खिलाफ इस प्रकार के दुष्प्रचार करेंगे। विपक्षी दलों के दुष्प्रचार का तथ्यों के साथ जवाब देना होगा। पार्टी कार्यकर्ता जनता को वास्तविकता से अवगत कराएं और उन्हें तथ्यों के साथ समझाएं कि भाजपा इस तरह का कोई कार्य नहीं करने वाली।

सत्ता और संगठन मध्यप्रदेश में भी कांग्रेस और विपक्षी दलों के इस नैरेटिव को रोकने के लिए और क्या कर सकता है, इस पर सभी विचार करें। ■



# योग से समाज में सकारात्मक बदलाव - पीएम मोदी



योग केवल एक विधा नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में, मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है।

इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं, एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग-ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है।

- विश्वभर में योगाभ्यास करने वाले लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।
- योग से सृजित वातावरण, ऊर्जा और अनुभव को महसूस किया जा सकता है।
- विश्व एक नई योग अर्थव्यवस्था के उभरने का साक्षी बन रहा है।
- विश्व योग को वैश्विक कल्याण के एक समर्थ संवाहक के रूप में देख रहा है।

- योग अतीत के बोझ से मुक्त करते हुए वर्तमान में जीने में सहायता करता है।
- योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
- योग अनुभव कराता है कि हमारा कल्याण हमारे आसपास के वैश्विक कल्याण से जुड़ा है।
- योग केवल एक विधा ही नहीं अपितु एक विज्ञान भी है।

## अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस

10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से, योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35 हजार लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में UN हेडक्वार्टर में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। भारत में आयुष विभाग ने योग practitioners के लिए Yoga Certification Board बनाया है। देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है। विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता

प्राप्त की है।

पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य convince हो रहा है। विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर्स से मिलता हूँ, जहां भी जाता हूँ, शायद ही कोई एकाध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न करता हो। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता, जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में योग सेंटर का उद्घाटन किया था। वहाँ योग बेहद पॉपुलर हो चुका है।

तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी योगा थेरेपी को शामिल किया गया है। सऊदी अरब ने तो योग को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल किया है। मंगोलिया में भी मंगोलियन योग फाउंडेशन के तहत कई योग स्कूल चलाये जा रहे हैं। यूरोपियन देशों में भी

योग का चलन तेजी से बढ़ा है। जर्मनी में आज करीब डेढ़ करोड़ लोग, योग practitioners बन चुके हैं। इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। वो कभी भारत नहीं आई थीं, लेकिन उन्होंने योग के प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आज विश्व के बड़े-बड़े institutions और universities में योग पर रिसर्च हो रही है, रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं।

बीते दस वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरों से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकॉनमी को आगे बढ़ते देख रही है। भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरल तक, योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है।

दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भारत में authentic योग सीखना है। आज योगा रिट्रीट बन रहे हैं। योगा रिजॉर्ट बन रहे हैं। Airports में, होटेल्स में

योग के लिए dedicated facilities बनाई जा रही हैं। मार्केट में योग के लिए डिजाइनर परिधान, एपेरल्स, equipment आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियाँ भी employee wellness initiatives के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम्स शुरू कर रही हैं। इन सबने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं।

The theme of this year's International Day of Yoga is 'Yoga for Self and Society'. The world is looking at Yoga as a powerful agent of global good. Yoga helps us live in the present moment, without baggage of the past. It connects us with ourselves and our deepest feelings. It brings about oneness of the mind, body and soul. Yoga helps us realise that our welfare is related to the welfare of the world around us. When we are peaceful within, we can also make a positive impact on the world.

योग केवल एक विधा नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में, मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं, एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग-ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसीलिए, आज आर्मी से लेकर स्पॉर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्राम्स में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है।

इससे productivity भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है, ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केन्द्रित कर सकें। यानि योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है।

योग की ये प्रेरणा हमारे सकारात्मक प्रयासों को ऊर्जा देती रहेगी। पूरे जम्मू-कश्मीर में, श्रीनगर में योग के प्रति आकर्षण है, उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं, ये जम्मू-कश्मीर के टूरिज्म को देने के लिए एक नई ताकत का अवसर बन गया है। जम्मू-कश्मीर में 50-60 हजार लोगों का योग कार्यक्रम में जुड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। ■



# मोदी जी ने योग को लोकप्रिय बनाया : डॉ. मोहन यादव



**योग** का अर्थ जुड़ाव है। मन और आत्मा का जुड़ाव। आत्मा का चेतना से जुड़ाव और हमारे खान-पान, रहन-सहन और आचार-विचार से भी योग का संबंध है। इस नाते योग से इस वर्ष श्रीअन्न को भी जोड़ा गया है। योग को लोकप्रिय बनाने के प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रयास भलीभूत हो रहे हैं। 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ में योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वानुमति से सभी राष्ट्रों ने स्वीकार किया। भारतीय संस्कृति की ध्वजा लहराई। यह भारत की उज्ज्वल, गरिमापूर्ण, गौरवपूर्ण संस्कृति और हजारों साल से चली आ रही आहार शैली को भी समर्थन था। शारीरिक दक्षता के लिए जहां योग की जरूरत है वहीं आहार भी आवश्यक है। हम सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय आहार शैली को फिर से लोकप्रिय बनाने का कार्य हो रहा है। हमारी पूजा पद्धति में गेहूँ का स्थान नहीं है बल्कि चावल और

अन्य मोटे अनाज उपयोग में लाये जाते हैं। यह सनातन संस्कृति का हिस्सा है। योग की अलग-अलग पद्धतियां रही हैं। समय-समय पर महान योगाचार्य हुए हैं। वैदिक काल से लेकर पतंजलि काल तक योग की मौजूदगी के प्रमाण मिलते हैं। इसमें ध्यान, धारणा और समाधि आदि समाहित हैं। आज योग पूरी दुनिया में फैल गया है।

मध्यप्रदेश में योग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। योग शिक्षकों को अन्य विषयों के शिक्षकों की तरह महत्व मिल रहा है। आयुर्वेद की दृष्टि से भी अहम फैसले लिए गए हैं। प्रदेश में 11 आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोलने का निर्णय इसी कड़ी में लिया गया है। मध्यप्रदेश की समृद्ध वन संपदा की दृष्टि से आयुर्वेद के क्षेत्र में मध्यप्रदेश नवीन आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के माध्यम से पूरे देश का ध्यान आकर्षित करेगा। ■

## मध्यप्रदेश आदर्श संगठन डॉ. महेन्द्र सिंह

मध्यप्रदेश के देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बूथ विजय संकल्प लेकर कार्य किया, वह निश्चित रूप से अनुकरणीय कार्य है, जिसका परिणाम यह रहा कि हम प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त कर सके हैं।

## चुनाव

जीतने के लिए किस तरह का संगठन होना चाहिए, यह मध्यप्रदेश से दूसरे राज्यों की सीखना चाहिए। कई राज्यों में चुनाव कार्य देखा है, लेकिन मध्यप्रदेश जैसे देवतुल्य कार्यकर्ता नहीं देखा। मध्यप्रदेश में कार्यकर्ताओं की बहुत अच्छी टीम है, जो दिए गए कार्यों को टीम भावना के साथ बहुत अच्छे से कार्यों को पूरा करते हैं। मध्यप्रदेश में पार्टी का आदर्श संगठन है, जिसकी देशभर में सराहना होती है। अन्य राज्यों को भी मध्यप्रदेश संगठन से प्रेरणा लेकर कार्य करना चाहिए। मध्यप्रदेश के देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बूथ विजय संकल्प लेकर कार्य किया, वह निश्चित रूप से अनुकरणीय कार्य है, जिसका परिणाम यह रहा कि हम प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त कर सके हैं। इसके लिए एक-एक कार्यकर्ता को बधाई एवं शुभकामनाएं। ■

# संकल्प - 2047 तक विकसित भारत

**इक्कीसवीं** सदी टेक्नोलॉजी की सदी है। मानव जीवन का शायद ही कोई ऐसा पहलु होगा जो टेक्नोलॉजी के प्रभाव से वंचित हो। एक तरफ जहाँ टेक्नोलॉजी मनुष्य को चाँद तक ले जाने का साहस देती है, वहीं दूसरी ओर **cyber security** जैसी चुनौतियाँ भी पैदा करती है। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि टेक्नोलॉजी का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे, समाज के हर व्यक्ति के सामर्थ्य को उजागर करे, सामाजिक असमानताओं को दूर करने में मदद करे, और मानवीय शक्तियों को सीमित करने की बजाय उनका विस्तार करे। यह केवल हमारी अभिलाषा नहीं, हमारा दायित्व होना चाहिए।

हमें टेक्नोलॉजी में एकाधिकार को सर्वाधिकार में बदलना होगा। हमें टेक्नोलॉजी को संहारक नहीं सृजनात्मक रूप देना होगा। तभी हम एक समावेशी समाज की नींव रख सकेंगे। भारत अपनी इस **human-centric approach** के जरिए एक बेहतर भविष्य के लिए प्रयास कर रहा है। **Artificial Intelligence** में भारत **National Strategy** बनाने वाले पहले कुछ देशों में शामिल है। इसी स्ट्रेटिजी के आधार पर हमने इस वर्ष **A.I. Mission** लॉन्च किया है। इसका मूल मंत्र है **"A.I. for All"** **Global Partnership for AI** के संस्थापक सदस्य और **lead chair** के रूप में हम सभी देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। पिछले वर्ष भारत की मेजबानी में की गई **G-20** समिट के दौरान हमने **A.I.** के क्षेत्र में **International Governance** के महत्व पर बल दिया। भविष्य में भी **A.I.** को **transparent, fair, secure, accessible** और **responsible** बनाने के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे।

ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत की **approach** चार सिद्धांतों पर आधारित है - **availability, accessibility, affordability and acceptability.** के अंतर्गत लिए गए सभी **commitments** को समय से पहले पूरा करने वाला पहला देश है। और हम 2070 तक **Net Zero** के तय लक्ष्य को पाने के अपने **कमिटमेंट** को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। हमें मिलकर आने वाले समय को **Green Era** बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए भारत ने **Mission LIFE** यानि **Lifestyle**



2047 तक विकसित भारत का निर्माण हमारा संकल्प है। हमारा **कमिटमेंट** है कि समाज का कोई भी वर्ग देश की विकास यात्रा में पीछे न छूटे। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है।

**For Environment** की शुरुआत की है। इस मिशन पर आगे बढ़ते हुए, 5 जून, पर्यावरण दिवस पर, एक **campaign** शुरू की है - **"एक पेड़ माँ के नाम"**। अपनी माँ से सभी प्यार करते हैं। इसी भाव से हम वृक्षारोपण को एक **Mass Movement with personal touch and global responsibility** बनाना चाहते हैं। मेरा आग्रह है कि आप सभी इसमें जुड़ें। मेरी टीम सभी के साथ इसके **डिटेल्स** साझा करेंगी।

2047 तक विकसित भारत का निर्माण हमारा संकल्प है। हमारा **कमिटमेंट** है कि समाज का कोई भी वर्ग देश की विकास यात्रा में पीछे न छूटे। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। वैश्विक अनिश्चितताओं और

तनाव में **Global South** के देशों को सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। भारत ने **Global South** के देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं को विश्व पटल पर रखना अपना दायित्व समझा है। इन प्रयासों में हमने अफ्रीका को उच्च प्राथमिकता दी है। हमें गर्व है कि भारत की अध्यक्षता में **G-20** ने **African Union** को स्थायी सदस्य बनाया। अफ्रीका के सभी देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास, स्थिरता और सुरक्षा में भारत योगदान देता आया है, और आगे भी देता रहेगा।

बैठक सभी देशों की प्राथमिकताओं के बीच गहरे **convergence** को दर्शाती है। हम इन सभी विषयों पर **G-7** के साथ संवाद एवं सहयोग जारी रखेंगे। ■

# तीसरी आर्थिक ताकत बनाने में कृषि की बड़ी भूमिका



किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब, इन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। तीसरे कार्यकाल की शुरुआत इन्हीं के सशक्तिकरण से की है।

सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला, किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। देशभर में गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हों, या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों-करोड़ों लोगों की मदद करेंगे।

- पीएम किसान की 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की 17वीं किस्त।
- स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र।
- दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि कोई चुनी हुई सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आ जाए।
- 21वीं सदी में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने में समूची कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका है।
- पीएम किसान सम्मान निधि दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना बनकर उभरी है।
- पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक पहुंचने के लिए प्रौद्योगिकी का सही इस्तेमाल किया गया है।
- दुनिया भर में हर खाने की मेज पर भारत का कोई न कोई खाद्यान्न या खाद्य उत्पाद हो।
- माताओं और बहनों के बिना खेती की कल्पना करना असंभव है।

**भारत** में 18वीं लोकसभा के लिए हुआ चुनाव, भारत के लोकतंत्र की विशालता को, भारत के लोकतंत्र के सामर्थ्य को, भारत के लोकतंत्र की व्यापकता को, भारत के लोकतंत्र के जड़ों की गहराई को दुनिया के सामने पूरे सामर्थ्य के साथ प्रस्तुत करता है। इस चुनाव में देश के 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। पूरी दुनिया में इससे बड़ा चुनाव कहीं और नहीं होता है, जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। जी-7 के सारे देशों के सारे मतदाताओं को मिला दें, तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे



डेढ़ गुना ज्यादा है। यूरोप के तमाम देशों को जोड़ दें, यूरोपियन यूनियन के सारे मतदाताओं को जोड़ दें, तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे ढाई गुना ज्यादा है। इस चुनाव में 31 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया है। ये एक देश में महिला वोटर्स की संख्या के हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये संख्या अमेरिका की पूरी आबादी के आसपास है। भारत के लोकतंत्र की यही खूबसूरती, यही ताकत पूरी दुनिया को आकर्षित भी करती है, प्रभावित भी करती है।

इस चुनाव में देश के लोगों ने जो जनादेश दिया है, वो वाकई अभूतपूर्व है। इस जनादेश ने एक नया इतिहास रचा है। दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि कोई चुनी हुई सरकार लगातार तीसरी बार वापसी करे। लेकिन इस बार भारत की जनता ने ये भी करके दिखाया है। ऐसा भारत में 60 साल पहले हुआ था, तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी। भारत जैसे देश में जहां युवा आकांक्षा इतनी बड़ी है, जहां जनता के अथाह सपने हैं, वहां लोग अगर किसी सरकार को 10 साल के काम के बाद फिर सेवा का अवसर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी Victory है, बहुत बड़ा विजय है और बहुत बड़ा विश्वास है। आपका ये विश्वास लगातार आपकी सेवा के लिए, देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देता है।

किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब, इन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। तीसरे कार्यकाल की शुरुआत इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला, किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। देशभर में गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हों, या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों-करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका, उन्हें सम्मान और आय के नए साधन, दोनों सुनिश्चित करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि, दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में सवा 3 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी एक करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नीयत

होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के, जनहित के काम होते हैं।

21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। हमें वैश्विक रूप से सोचना होगा, ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना होगा। हमें दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनना है। और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है। बनारस का लंगड़ा आम, जौनपुर की मूली, गाजीपुर की भिंडी, ऐसे अनेक उत्पाद आज विदेशी मार्केट में पहुंच रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब बनने से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और उत्पादन भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का होने लगा है। अब हमें पैकेज्ड फूड के ग्लोबल मार्केट में देश को नई ऊंचाई पर ले जाना है और दुनिया की हर डायनिंग टेबल पर भारत का कोई न कोई खाद्यन्न या फूड प्रॉडक्ट होना ही चाहिए। इसलिए हमें खेती में भी जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट वाले मंत्र को बढ़ावा देना है। मोटे अनाज-श्री अन्न का उत्पादन हो, औषधीय गुण वाली फसल हो, या फिर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना हो, पीएम किसान समृद्धि केंद्रों के माध्यम से किसानों के लिए एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम विकसित किया जा रहा है।

माताओं-बहनों के बिना खेती की कल्पना भी असंभव है। इसलिए, अब खेती को नई दिशा देने में भी माताओं-बहनों की भूमिका का विस्तार

किया जा रहा है। नमो ड्रोन दीदी की तरह ही कृषि सखी कार्यक्रम ऐसा ही एक प्रयास है। हमने आशा कार्यकर्ता के रूप में बहनों का काम देखा है। हमने बैंक सखियों के रूप में डिजिटल इंडिया बनाने में बहनों की भूमिका देखी है। अब हम कृषि सखी के रूप में खेती को नई ताकत मिलते हुए देखेंगे। 30 हजार से अधिक सहायता समूहों को कृषि सखी के रूप में प्रमाणपत्र दिए गए हैं। अभी 12 राज्यों में ये योजना शुरू हुई है। आने वाले समय में पूरे देश में हजारों समूहों को इससे जोड़ा जाएगा। ये अभियान 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने में भी मदद करेगा।

पिछले 10 वर्षों में किसानों के लिए सरकार ने पूरे समर्पण भाव से काम किया है। मछली पालकों की आय बढ़ाने के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। पीएम मत्स्य संपदा योजना से सैकड़ों किसानों को लाभ हो रहा है। उन्हें अब किसान क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा मिल रही है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को भी जबरदस्त सफलता मिल रही है। जो घर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़े हैं उनमें से ज्यादातर को डबल फायदा हुआ है। उनका बिजली बिल तो जीरो हो ही गया है, 2-3 हजार रुपए की कमाई भी होने लगी है।

बीते 10 सालों में शहर और आसपास के गांवों में कनेक्टिविटी का जो काम हुआ है, उससे भी बहुत मदद हुई है। ■

## प्रदेश में बना इतिहास



**भाजपा** कार्यकर्ता आधारित संगठन है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपना बूथ सबसे मजबूत और बूथ जीतने के संकल्प को लेकर कार्य किया है, जिसका परिणाम है कि प्रदेश की 29 सीटों पर पार्टी को प्रचण्ड विजय मिली है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक बूथ पर पार्टी प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ा है और यह ऐतिहासिक दिन आया है। हर बूथ पर कार्यकर्ताओं ने जो अथक मेहनत व परिश्रम से पार्टी को विजय दिलाई है, उसकी देश भर में प्रशंसा हो रही है। मध्यप्रदेश की जनता का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी पर इतना विश्वास ही है कि किसी भी अन्य पार्टी को कोई मौका नहीं दिया। भाजपा सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा पर कार्य करती है। भाजपा के हर कार्यकर्ता का पूरा सम्मान रखा जाएगा और समूचे मध्यप्रदेश के हर क्षेत्र का समुचित विकास किया जाएगा। ■



# 18वीं लोकसभा सपनों को पूर्ण करेगी - पीएम मोदी

- 17वीं लोकसभा में कई परिवर्तनकारी विधायी पहल देखी गई।
- संसद सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा का केंद्र है।

**17वीं** लोकसभा में नारी शक्तिवन्दन अधिनियम 2023, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, Consumer Protection Bill, Direct Tax, विवाद से विश्वास विधेयक, सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय महत्व के ऐसे कितने ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कानून 17वीं लोकसभा में सदन ने पारित किए हैं और देश के लिए एक मजबूत नींव बनाई है। जो कार्य आजादी के 70 साल में नहीं हुए, इस सदन ने इसको करके दिखाया।

लोकतंत्र की लंबी यात्रा में कई पड़ाव आते हैं। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब हमें कीर्तिमान स्थापित करने का सौभाग्य मिलता है। 17वीं लोकसभा में उपलब्धियां, देश आज भी और भविष्य में उसका गौरव करेगा। देश अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में जब हर तरह से प्रयास हो रहे हैं, तो नया संसद भवन भी अमृतकाल के भविष्य को लिखने का काम करेगा।

लोकसभा में हम पेपरलेस डिजिटल व्यवस्था से काम कर रहे हैं। पहली बार सभी माननीय सांसदों को briefing के लिए एक व्यवस्था खड़ी की। इससे सभी माननीय सांसदों को भी आवश्यक reference material मिला। उसके कारण सदन की चर्चा अधिक पुष्ट हुई और ये एक अच्छा initiative था, जिसने सांसदों में भी विश्वास पैदा किया था, मैं भी कुछ कह



लोकतंत्र की लंबी यात्रा में कई पड़ाव आते हैं। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब हमें कीर्तिमान स्थापित करने का सौभाग्य मिलता है। 17वीं लोकसभा में उपलब्धियां, देश आज भी और भविष्य में उसका गौरव करेगा।

देश अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में जब हर तरह से प्रयास हो रहे हैं, तो नया संसद भवन भी अमृतकाल के भविष्य को लिखने का काम करेगा। लोकसभा में हम पेपरलेस डिजिटल व्यवस्था से काम कर रहे हैं।

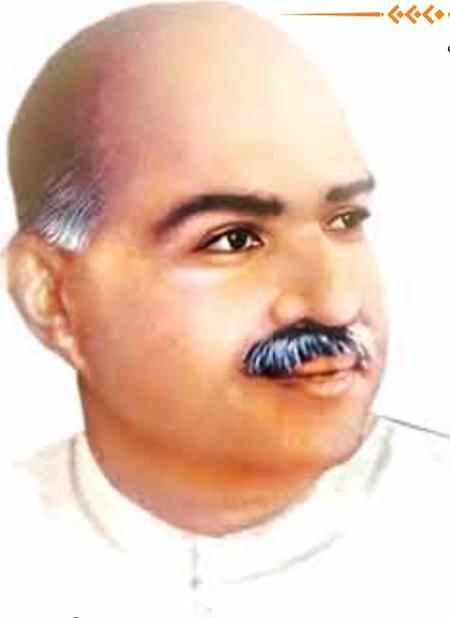
सकता हूँ, मैं भी अपने तर्क दे सकता हूँ। एक अच्छी व्यवस्था को विकसित किया। जी 20 भारत की सफलता का एक महत्वपूर्ण पृष्ठ है।

ये हमारा भवन, ये सिर्फ चार दीवारें नहीं है। हमारा ये संसद 140 करोड़ देशवासियों की आशा का केंद्र है। संसद की कार्यवाही, जवाबदेही और आचरण हमारे देशवासियों के मन में लोकतंत्र के प्रति उनकी जो निष्ठा है,

उसको और अधिक मजबूत बनाती है। 17वीं लोकसभा, उसकी productivity, 25 साल के highest level पर 97 प्रतिशत रही। कोरोना जैसे मुश्किल कालखंड में भी सदन का काम रूका नहीं। कोरोना काल में सदन ने 170 प्रतिशत productivity, ये अपने आप में दुनिया के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है।

# डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक आदर्श नेता

जब वह पहली बार हिन्दू महासभा के अधिवेशन में उपस्थित हुए तो वह हिन्दी में बोल नहीं सके। परन्तु उन्होंने वायदा किया कि वह जल्द इस भाषा को सीख लेंगे और अगले वर्ष उन्होंने हिन्दी में भाषण दिया।



**ब**गाल के बाहर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अधिकांश भाषण हिन्दी में होते थे। जब वह पहली बार हिन्दू महासभा के अधिवेशन में उपस्थित हुए तो वह हिन्दी में बोल नहीं सके। परन्तु उन्होंने वायदा किया कि वह जल्द इस भाषा को सीख लेंगे और अगले वर्ष उन्होंने हिन्दी में भाषण दिया। निःसन्देह उनसे हिन्दी में सही व्याकरण के उपयोग करने की आशा नहीं की जा सकती थी। परन्तु उन्होंने अपने आप को सही ढंग से अभिव्यक्त किया और अधिकांश अवसरों पर उनकी भाषा अत्यंत शक्तिशाली होती थी।

## जब उन्होंने हिन्दी पर आग्रह किया

उन्होंने भारतीय जनसंघ के उद्घाटन सत्र का अध्यक्षीय भाषण अंग्रेजी में लिखा। परन्तु वह प्रतिनिधियों को इसकी प्रतियां हिन्दी में वितरित करना चाहते थे। परन्तु समय बहुत कम था। यह 20 अक्टूबर का दिन था। भाषण अगले

दिन प्रातः 10 बजे पढ़ा जाना था। इसके अलावा विषय समिति की बैठक भी 26 तारीख को होनी थी। परन्तु, वह इस विषय पर बहुत उत्सुक थे। फलस्वरूप, न केवल अध्यक्षीय भाषण, बल्कि घोषणापत्र को भी हिन्दी में अनुवादित किया और अर्जुन प्रेस के कर्मचारियों की अपार उत्साह के कारण दोनों को समय पर छाप कर प्रतिनिधियों को पेश किया गया। किन्तु, डा. मुखर्जी जी ने भाषण नहीं पढ़ा। जैसा कि रिवायत थी, उसके अनुसार उनका मुंहजबानी भाषण अनुवादित भाषण से कहीं अधिक प्रभावशाली था।

हिन्दी भाषणों में डॉ. मुखर्जी ने संस्कृत शब्दों का उपयोग किया। अतः उन्हें कभी भी सही शब्द चुनने में कठिनाई नहीं आई। उनकी संस्कृत शैली के कारण उनकी भाषा एक दम शुद्ध थी। किन्तु, उन्होंने 'सर्वनाश' शब्द का उपयोग नहीं किया, बल्कि 'खतरनाश' कहना बेहतर समझा। यह वह शब्द था, जिसे उन्होंने स्वयं गढ़ा था। वह हमेशा सोचा करते थे कि वह गलत शब्द का उपयोग कर रहे हैं। परन्तु, वह गलती बताने में हिचकिचाहट महसूस करते थे। एक दिन, निःसंदेह, जब आम बातचीत चल रही थी तो भाषा बहस का विषय बन गया तो मैंने 'खतरनाश' शब्द को सही शब्द नहीं बताया। सही होता, अगर वह 'सर्वनाश' या 'सत्यानाश' का प्रयोग करते। उन्होंने इस सुझाव के लिए मुझे धन्यवाद दिया, परन्तु कहा कि क्या तुम्हें महसूस नहीं होता है कि 'खतरनाश' और 'सर्वनाश' के बीच दो शब्दों के अंतर की छाया है? हां, अन्तर तो है।

यहीं वह अन्तर था जिससे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के अनेक विरोधी नेताओं से अलग-थलग दिखाई पड़ते थे। डॉ. मुखर्जी सतर्क थे और हमेशा ही सरकार और दिग्गजों का ध्यान गलत नीतियों व कदमों की ओर दिलाया करते थे। परन्तु वह न तो तबाही के पैगंबर थे, न ही 'साइनिक' 'पागल' थे। अतः उन्होंने जानबूझकर 'खतरनाश', 'सर्वनाश'

शब्द चुने जिनका मतलब पूर्ण 'तबाही' से था, जो फारसी और संस्कृत के मिले-जुले शब्दों से निकलता था। यदि इस अन्तर को समझ लिया जाए और इस विरोध के अन्तर को मान लिया जाए तो सरकार की बेकार की आलोचना नहीं होगी, बल्कि राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में रचनात्मक योगदान मिल जाएगा।

किसी शब्द का विरोध काम गुमराह करना नहीं होता है, बल्कि नेतृत्व करना बन जाता है। कामकाज नकारात्मक नहीं, बल्कि सकारात्मक होना चाहिए। इससे सरकार को कभी आलसी या लापरवाह नहीं बनने देना चाहिए। परन्तु इससे लोगों में भय भी पैदा नहीं होना चाहिए और न ही मनोबल गिरना चाहिए।

## जनसंघ ने कभी अपना सिर झुकने नहीं दिया

प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस ने पूरी सीटें अपने पक्ष में कर लीं। अधिकांश विरोधी नेता हार गए। ऐसी पार्टियां जिन्होंने वायदा किया था कि वे सरकार परिवर्तन पर देश की तस्वीर बदल देंगे, हार गईं। ऐसे वातावरण में एक व्यक्ति डा. मुखर्जी के पास पहुंचा और कहा कि भारत में लोकतंत्र का भविष्य अंधकारमय है। डॉ. मुखर्जी ने उससे दो प्रश्न पूछे।

1. क्या तुम्हारा लोकतंत्र में विश्वास है?
2. क्या तुम सक्रिय रूप से राजनीति में कार्य करने का संकल्प करते हो।

उस सज्जन ने 'हां' में जवाब दिया। इस पर डॉ. मुखर्जी ने कहा तो अब बताओं, कैसे लोकतंत्र का भविष्य अंधकारमय हो सकता है और यह भी जोड़ा कि यह तभी अंधकारमय होगा यदि हम काम न करें या आपको विश्वास ही न हो। जहां विश्वास रहता है, वहां अंधकार हो ही नहीं सकता। यह उज्ज्वल ही होगा।

मैंने देखा कि वास्तव में यही वह व्यक्ति है जो नेतृत्व कर सकता है। हम कभी-कभी लोगों से मिलते हैं, जिन्हें 'नेता' कहा जाता है परन्तु, शायद ही वे लोगों में विश्वास पैदा कर सकते हों। इसके विपरीत यदि आप उनके पास पूर्ण विश्वास के साथ पहुंचे तो आप आत्मसंतोष ही लेकर लौटें। डॉ. मुखर्जी उन लोगों में से ऐसे व्यक्ति नहीं थे। जब हम उनसे मिले तो उन्होंने पराजय का रोना नहीं रोया। उन्होंने कहा कि यदि हम सफल होना चाहते हैं तो हमें कठिन परिश्रम करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि जनसंघ ने कम से कम बेहतर कर दिखाया है। शेष सभी अन्य पार्टियों के सिर झुक गए परन्तु आपका अध्यक्ष सफल होकर आया है। हां, किसी की निराशा तस्वीर की उज्ज्वल आयाम होता है और यही हमारे भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए प्रेरित करता है। ■



# डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी-एकता एवं अखंडता के अग्रदूत

■ श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की एकता एवं अखंडता के अग्रदूत थे। विकसित, आत्मनिर्भर और मजबूत भारत बनना ही श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

■ श्रद्धेय मुखर्जी जी ने जम्मू-कश्मीर में धारा 370 लगाने और परमिट सिस्टम का कड़ा विरोध किया तथा नेहरू जी की कैबिनेट से त्याग-पत्र देते हुए नारा दिया कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे।

■ डॉ. मुखर्जी जी ने धारा 370 की समाप्ति के लिए और देश की अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, पुलिस हिरासत में उनकी संदिग्ध मृत्यु हुई लेकिन उनकी पूज्य माताजी द्वारा जांच की मांग के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जांच करवाने से इनकार कर दिया।

■ इसी से पता चलता है कि उस समय देश में कैसा प्रजातंत्र रहा होगा और कांग्रेस के प्रधानमंत्री उस समय कैसा बर्ताव किया करते थे?

■ भारत विभाजन के दौरान कांग्रेस नेताओं से समझौते के समय मुस्लिम लीग ने समूचा पंजाब और बंगाल लेने की ठान ली थी, उस समय श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जन-आंदोलन खड़ा कर जनता को जागृत किया था, जिसके कारण पंजाब और बंगाल अखंड भारत का हिस्सा बने।

■ डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सत्ता के लिए राजनीति में नहीं आए थे बल्कि उन्होंने विचारधारा के लिए सत्ता का त्याग कर दिया।

■ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आह्वान है कि "एक पेड़ मां के नाम" कार्यक्रम के अंतर्गत श्री श्यामा प्रसाद



श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक विचारधारा के लिए अपना जीवन खपा दिया। वे सत्ता के लिए राजनीति में नहीं आए थे बल्कि उन्होंने विचारधारा के लिए सत्ता का त्याग कर दिया। श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार में मंत्री थे, लेकिन विचारधारा के लिए उन्होंने मंत्री पद का भी त्याग कर दिया।

इसके अलावा उन्होंने जवाहर लाल नेहरू जी की पहली कैबिनेट में मंत्री रहते हुए नेहरू जी की छद्म धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध प्रखर आवाज उठाई और कहा कि वह मुस्लिम लीग तथा साम्प्रदायिक ताकतों के सामने घुटने टेकने से मत भिन्नता रखते हैं।

मुखर्जी के बलिदान दिवस से उनकी जन्म जयंती तक लाखों लोग अपने परिवार के नाम पर पेड़ लगाएंगे।

■ जिस तरह एक मां पूरे परिवार का संरक्षण और पोषण करती है, ठीक उसी प्रकार एक पेड़ सारे समाज को पोषित और संरक्षित करता है। इसलिए भाजपा "एक पेड़ मां के नाम" कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है।

■ मेरी कार्यकर्ताओं से अपील है कि सभी कार्यकर्ता बागवान या बगीचों में "एक पेड़ मां के नाम" अवश्य लगाएं और पर्यावरण

को सहेजने में अपनी भूमिका निभाएं।

**भारतीय** जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 23 जून 1953 को श्रीनगर जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी अंतिम सांस ली थी और यह रहस्यमयी परिस्थिति हम सभी के लिए आज तक एक प्रश्नचिह्न बना हुआ है। श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान देशभक्त, शिक्षाविद् और सामाजिक न्याय के पुरोधा थे।



श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति रहे। श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी एवं एक महान शिक्षाविद् थे और साथ ही देशभक्ति की भावना के कारण उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। यह कहा जा सकता है कि वर्तमान पंजाब और पश्चिम बंगाल श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के कारण ही भारत का अभिन्न अंग है। भारत के विभाजन के दौरान कांग्रेस नेताओं से समझौते के समय मुस्लिम लीग ने समूचा पंजाब और बंगाल लेने की ठान ली थी, उस समय श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जन-आंदोलन खड़ा कर जनता को जागृत किया था, जिसके कारण पंजाब और बंगाल अखंड भारत का हिस्सा बने।

श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक विचारधारा के लिए अपना जीवन खपा दिया। वे सत्ता के लिए राजनीति में नहीं आए थे बल्कि उन्होंने विचारधारा के लिए सत्ता का त्याग कर दिया। श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार में मंत्री थे, लेकिन विचारधारा के लिए उन्होंने मंत्री पद का भी त्याग कर दिया। इसके अलावा उन्होंने जवाहर लाल नेहरू जी की पहली कैबिनेट में मंत्री रहते हुए नेहरू जी की छद्म धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध प्रखर आवाज उठाई और कहा कि वह मुस्लिम लीग तथा साम्प्रदायिक ताकतों के सामने घुटने टेकने से मत भिन्नता रखते हैं। श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर भी प्रखर आवाज उठाते हुए धारा 370 लगाने का विरोध किया एवं इसके विरोध में श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू जी की कैबिनेट से त्याग-पत्र देते हुए नारा दिया कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे और इसी नारे के साथ श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सत्याग्रह किया। धारा 370 के तहत जम्मू-कश्मीर जाने के लिए परमिट बनाना पड़ता था लेकिन श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध करते हुए परमिट नहीं लिया और उन्हें जम्मू-कश्मीर के बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया गया। श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की गिरफ्तारी के लगभग एक महीने बाद उनकी जेल में संदेहास्पद स्थिति में उनका देहावसान हो गया। श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मां ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से इस घटना की जांच कराने की मांग करते हुए कहा था कि मुझे नेहरू की दलील नहीं, बल्कि अपने बेटे की मौत की जांच चाहिए लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जांच करवाने से इनकार कर दिया।

जिस लड़ाई के लिए श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया, भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अविरल

रूप से उस लड़ाई को आगे बढ़ाया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 6 अगस्त 2019 को धारा 370 को धराशायी कर दिया और एक देश में 'एक निशान, एक विधान और एक प्रधान' के नारे को स्थापित किया। श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नीतियों को मानने वाले करोड़ों लोगों ने भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस लड़ाई को आगे बढ़ाया और आज हम इस निर्णायक मोड़ तक पहुंच पाए हैं। उनकी संदेहास्पद मृत्यु की जांच तक नहीं की गई, इसी से पता चलता है कि उस समय देश में कैसा प्रजातंत्र रहा होगा और कांग्रेस के प्रधानमंत्री कैसा बर्ताव किया करते थे? लोकतंत्र मजबूत होते-होते आज यहां तक पहुंचा है और आज श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार और कार्य को आगे बढ़ाने के लिए करोड़ों कार्यकर्ता बलिदान देने के लिए तैयार हैं।

भाजपा हर वर्ष इस बलिदान दिवस को मनाती है और इस वर्ष हमने इसे पर्यावरण से भी जोड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आव्हान है कि 'एक पेड़ मां के नाम' कार्यक्रम के अंतर्गत श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से उनकी जन्म जयंती तक लाखों लोग अपने परिवार के नाम पर पेड़ लगाएं। जिस तरह एक मां पूरे परिवार का संरक्षण और पोषण करती है, ठीक उसी प्रकार एक पेड़ सारे समाज को पोषित और संरक्षित करता है। इसलिए भाजपा 'एक पेड़ मां के नाम' कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। सभी कार्यकर्ता बागवान या बगीचों में एक पेड़ मां नाम अवश्य लगाएं और पर्यावरण को सहेजने में अपनी भूमिका निभाएं। विकसित, आत्मनिर्भर और मजबूत भारत बनाना ही श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ■

## 175 से ज्यादा देशों ने अपनाया योग - विष्णुदत्त शर्मा



### अंतरराष्ट्रीय

योग दिवस पर 175 देशों ने योग कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने दुनिया के देशों को स्वस्थ रहने के लिए योग को अपनाने की सलाह दी थी और दुनिया के देशों ने हमारी भारतीय संस्कृति के प्रतीक योग को आत्मसात किया। आज पूरे विश्व में योग की यश-पताका फहरा रही है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर भाजपा द्वारा प्रदेशभर में बूथ स्तर पर योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए। यूं तो अनादिकाल से ही योग भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। किसी भी धार्मिक अथवा आध्यात्मिक साधना की सिद्धि से पूर्व योगाभ्यास द्वारा शरीर को साधने का कार्य योग द्वारा किया जाता है। महर्षि पतंजलि सहित अनेक योगशास्त्रियों ने योग के सरलीकरण का कार्य किया, ताकि आम जनमानस के लिए योग सुलभ हो सके। वर्तमान कालखण्ड में भारत के गौरव की यश-पताका को निरन्तर विश्व में लहराने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस भारतीय ज्ञान-मनीषा को समूची दुनिया में लोकप्रिय एवं नवीन पहचान दिलाने का कार्य किया है। आज पूरा विश्व योग के साथ ही भारत के वैभव और निरन्तर प्रगति की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहा है। मोदी जी के प्रयासों से ही विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के योग के संदेश को दुनिया के अन्य देश अपनाकर अपने आपको स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने श्रीनगर में योग कर योग के साथ-साथ शांति का भी संदेश दिया। सामाजिक संस्थाओं से लेकर स्थानीय लोगों ने निरोगी काया रखने का संदेश दिया है। योग के साथ-साथ स्वच्छता को भी अपनाकर आगे बढ़ाकर नया इतिहास रचेंगे। ■

# डॉ. मुखर्जी - निष्काम, निस्वार्थ, निष्कपट राज-योगी



**डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी बंगाली भद्रलोक के ऐसे प्रभावशाली परिवार में जन्मे थे, जो उस समय बंगाल में अपनी बौद्धिकता के लिए विख्यात था। मात्र 33 साल की उम्र में डॉ. मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए थे।**

इतनी कम उम्र में कुलपति बनने वाले वो पहले भारतीय थे। उनके पिता भी कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुलपति रह चुके थे, लेकिन डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने यह मुकाम अपनी योग्यता और विद्वता से हासिल किया था।



विष्णुदत्त शर्मा

**जम्मू** -कश्मीर को भारतीय संविधान के दायरे में लाने और एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान (झंडा) के विरोध में सबसे पहले आवाज उठाने वाले भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 23 जून को बलिदान दिवस है। कश्मीर से विरोधाभासी प्रावधानों की

समाप्ति के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया, लेकिन चाहकर भी उनका यह स्वप्न उनके जीते जी पूरा नहीं हो पाया और रहस्यमय परिस्थितियों में 23 जून 1953 को उनकी मृत्यु हो गई। उनका यह स्वप्न स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्ष बाद तब पूरा हुआ जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अगस्त 2019 में संसद में संविधान के अनुच्छेद 370 एवं 35-ए को समाप्त करने का बिल पारित कराया। लेकिन डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी का भारत और भारतीयों के लिए योगदान सिर्फ जम्मू-कश्मीर तक सीमित नहीं है। डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व का समग्र विश्लेषण उन्हें उन युग-पुरुषों में स्थापित करता है, जो वर्तमान की देहलीज पर

बैठकर भविष्य की सामाजिक और राजनीतिक गणनाओं का आंकलन करने में समर्थ थे। पचास के दशक में, जनसंघ की स्थापना के मंगलाचरण के दौर में भारत की भावी राजनीति और सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने जो चिंताएं व्यक्त की थीं, वो आज पूरी विकरालता और भयावहता के साथ सिर उठाती दिखाई देती हैं।

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी बंगाली भद्रलोक के ऐसे प्रभावशाली परिवार में जन्मे थे, जो उस समय बंगाल में अपनी बौद्धिकता के लिए विख्यात था। मात्र 33 साल की उम्र में डॉ. मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए थे। इतनी कम उम्र में कुलपति बनने वाले वो पहले भारतीय थे। उनके पिता भी कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुलपति रह चुके थे, लेकिन डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने यह मुकाम अपनी योग्यता और विद्वता से हासिल किया था। शिक्षा के शिखर से उतरकर भारतीय राजनीति में उनका पदार्पण गहन राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए हुआ था। डॉ. मुखर्जी उस समय बंगाल में जारी मुस्लिम लीग की विभाजनकारी और सांप्रदायिक राजनीति से काफी नाराज और विचलित थे। मुस्लिम लीग की राजनीति बंगाल को एक और विभाजन की ओर ले जा रही थी। मुस्लिम लीग सुनियोजित तरीके से ब्रिटिश-शासन की मदद से भारत के पूर्वी हिस्सों में हिन्दुओं को हाशिए पर ढकेल रही थी। डॉ. मुखर्जी ने संकल्प लिया था कि मुस्लिम लीग की कट्टरता के खिलाफ वो हिन्दू-समाज को जागृत करेंगे। इस लड़ाई को वो सामाजिक और राजनीतिक, दोनों मोर्चों पर लड़ना चाहते थे। इसी के मद्देनजर उन्होंने बंगाल में सक्रिय कृषक प्रजा पार्टी के प्रमुख फजल-उल-हक और बंगला के जाने-माने महाकवि काजी नजरूल इस्लाम के साथ इस काम को आगे बढ़ाया।

हिन्दू एकता और देश की अखंडता पर आसन्न खतरों ने उन्हें हिंदू महासभा की ओर आकर्षित किया, जिसका नेतृत्व वीर सावरकर करते थे। 1939 में वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बन गए। अध्यक्ष के रूप में उन्होंने घोषणा की कि संयुक्त भारत के लिए तत्काल समग्र स्वतंत्रता हासिल करना हिंदू महासभा का मूल उद्देश्य है। गौरतलब है कि महात्मा गांधी ने भी हिंदू महासभा में उनकी सक्रियता का स्वागत किया था। गांधी जी चाहते थे कि पीडित मदनमोहन मालवीय के निधन के बाद हिंदू-समाज के नेतृत्व के लिए किसी प्रभावशाली

व्यक्ति को आगे आना चाहिए। गांधी जी डॉ. मुखर्जी को पं. मदनमोहन मालवीय के विकल्प के रूप में देखते थे और उनके राष्ट्रवादी रूख तथा निष्ठा पर पूरा भरोसा करते थे। हिन्दू महासभा में शामिल होने के बाद जब डॉ. मुखर्जी गांधी जी से मिलने पहुंचे, तो दोनों के बीच दिलचस्प संवाद हुआ। डॉ. मुखर्जी ने गांधी जी से कहा कि आप मेरे हिन्दू महासभा में शामिल होने पर खुश नहीं होंगे, तो गांधीजी ने उनसे कहा था कि 'सरदार पटेल हिन्दू मनोमस्तिष्क से ओतप्रोत कांग्रेसमैन हैं, आप हिन्दू महासभाई हो, जिसका हृदय कांग्रेस का है। यही देश के हित में है'। महात्मा गांधी के कहने पर ही पं. नेहरू ने डॉ. मुखर्जी को अपनी कैबिनेट में शामिल किया था। पं. नेहरू की कैबिनेट में रहते हुए डॉ. मुखर्जी ने कई बड़े काम किए। पं. नेहरू भी उनके कामों के कायल थे, लेकिन पाकिस्तान, कश्मीर या शरणार्थियों जैसे मसलों में दोनों के बीच व्यापक और गहरी राजनीतिक असहमति थी। धारा 370, हिंदू कोड बिल और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर भी पं. नेहरू से उनकी पटरी कभी भी नहीं बैठ पाई। ये ही वो कारण हैं, जो अन्ततः नेहरू कैबिनेट से उनके इस्तीफे का कारण बने।

आजादी के पहले बंगाल में मुस्लिम लीग के प्रभुत्व के विरुद्ध डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जबरदस्त संघर्ष किया और देश को होने वाले नुकसान से बचा लिया। विभाजन के समय भी डॉ. मुखर्जी ने देश की जनता और नेतृत्व को आगाह किया था- 'पाकिस्तान साम्प्रदायिक समस्या का कोई हल नहीं है। इससे वह और उग्र होगी, जिसका परिणाम गृहयुद्ध होगा। हमें इससे आंखें नहीं मूंदना चाहिए कि पाकिस्तान की लालसा का स्रोत वस्तुतः शासन सत्ता के रूप में इस्लाम की पुनः प्रतिष्ठा करने की इच्छा है।' 1953 में जनसंघ के पहले अधिवेशन में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की कश्मीर नीति का विरोध करते हुए कहा था कि एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। नेहरू-सरकार की नीतियों से असहमत होने के बाद लोकसभा में दिया गया उनका भाषण ऐतिहासिक है। अगस्त 1952 में लोकसभा में कश्मीर के मुद्दे पर भाषण देते हुए डॉ. मुखर्जी ने कहा था- 'दुनिया को यह पता होना चाहिए कि भारत महज एक थ्योरी या परिकल्पना नहीं है, बल्कि एक यथार्थ है... एक ऐसा देश जहां हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और सभी बिरादरी के लोग बगैर किसी भय के समान अधिकारों के साथ रह सकेंगे। यही हमारा संविधान है, जिसे हमने बनाया है और पूरी शिद्दत, निष्ठा और ताकत से लागू करने जा रहे हैं।' डॉ. मुखर्जी मानते थे कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम सब एक हैं... इसलिए धर्म के आधार पर वे विभाजन के कट्टर विरोधी थे। वो मानते थे कि विभाजन संबंधी परिस्थितियां ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से उत्पन्न हुई थीं। वे कहते

थे- आधारभूत सत्य यह है कि हम सब एक हैं... हममें कोई अंतर नहीं है... हम एक ही रक्त के हैं, एक ही भाषा, एक ही संस्कृति और एक ही हमारी विरासत है...।

डॉ. मुखर्जी महान शिक्षाविद्, निराभिमानी देशभक्त, राजनीतिक चिंतक और सामाजिक दृष्टा थे। प्रखर राष्ट्रवादी के रूप में वो हमेशा देश में पहली पायदान पर खड़े मिलेंगे। डॉ. मुखर्जी सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक और सिद्धांतवादी थे। राजनीति में उनकी सक्रियता के मायने उन आदर्शों का परिपालन था, जो मनुष्यता के कवच का काम करते हैं। सार्वजनिक जीवन में उनकी राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का निस्वार्थ और त्याग-जनित लोकार्पण उन्हें असामान्य बनाता है। वो पं. नेहरू की नीतियों के मुखर आलोचक और विरोधी थे।

वो महज एक अलग राजनीतिक विचारधारा के पोषक होने के नाते नेहरू का विरोध नहीं करते थे। वे एक सुविचारित और भारतीय संस्कृति के अनुकूल राजनीतिक दर्शन के प्रणेता थे और उसी के निर्धारित मानदंडों के आधार पर विषयों को तौल कर विरोधियों से वाद-विवाद करते थे। विरोध के लिए विरोध और बोलने के लिए बोलना, उनके राजनीतिक आचरण से कोसों दूर

था। संसदीय शिष्टाचार के वो कट्टर अनुपालक थे। उनकी आलोचनाएं रचनात्मक होती थी और सुझाव विचारपूर्ण होते थे। इसीलिए वो अपने समकालीन सांसदों में सबसे ज्यादा सम्मानित और विश्वसनीय नेता थे। कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता उनके गंभीर परामर्शों को अनसुना नहीं करते थे। राजनीतिक मलिनताओं के बीच उनके व्यक्तित्व की प्रखरता अलग ही दमकती थी। वो किस मिट्टी के बने थे, इसकी झलक 07 जनवरी 1939 को लिखे डायरी के उस पन्ने में मिलती है... जिसकी इबारत उपासना के मार्मिक उदगारों में उदघाटित होती है-

“हे प्रभु... मुझे निष्ठा, साहस, शक्ति, और मन की शांति दीजिए... मुझे दूसरों का भला करने की हिम्मत, और दृढ़ संकल्प दीजिए... मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए कि सुख में भी और दुख में भी आपको याद करता रहूँ... और आपके स्नेह में पलता रहूँ... हे प्रभु... मुझे से हई गलतियों के लिए क्षमा कीजिए और मुझे सत्प्रेरणा देते रहिए...।”

राजनीति में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे निष्काम, निस्वार्थ, निष्कपट राज-योगी का अवतरण बिरले ही होता है...।

(लेखक- म.प्र. भाजपा के अध्यक्ष व खजुराहो सांसद हैं)

## 60 साल बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री - श्री विष्णुदत्त शर्मा



**देश** की आजादी के बाद श्री नरेन्द्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले गैर कांग्रेसी पहले राजनेता हैं। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री जी के प्रति देश की जनता के अटूट विश्वास, प्रेम और आशीर्वाद से ही संभव हो सकी है। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण के लिए पिछले दस वर्षों में देश के अंदर जो कार्य किया है व मध्यप्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किए हैं उसकी वजह से मध्यप्रदेश में भाजपा ने सभी 29 लोकसभा सीटों जीतकर एक नया इतिहास बनाया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा ने मध्यप्रदेश में सभी सीटों जीतने का जो इतिहास बनाया है, इसके पीछे भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, लगन व परिश्रम है। भाजपा के बृथ स्तरीय कार्यकर्ताओं ने दिन-रात मेहनत कर घर-घर संपर्क किया और भाजपा सरकार की उपलब्धियां जनता को बताई, इसी का परिणाम है लोकसभा में भाजपा को ऐतिहासिक बहुमत मिला है।

# स्वत्व, स्वाभिमान और राष्ट्र के लिए जीवन का बलिदान



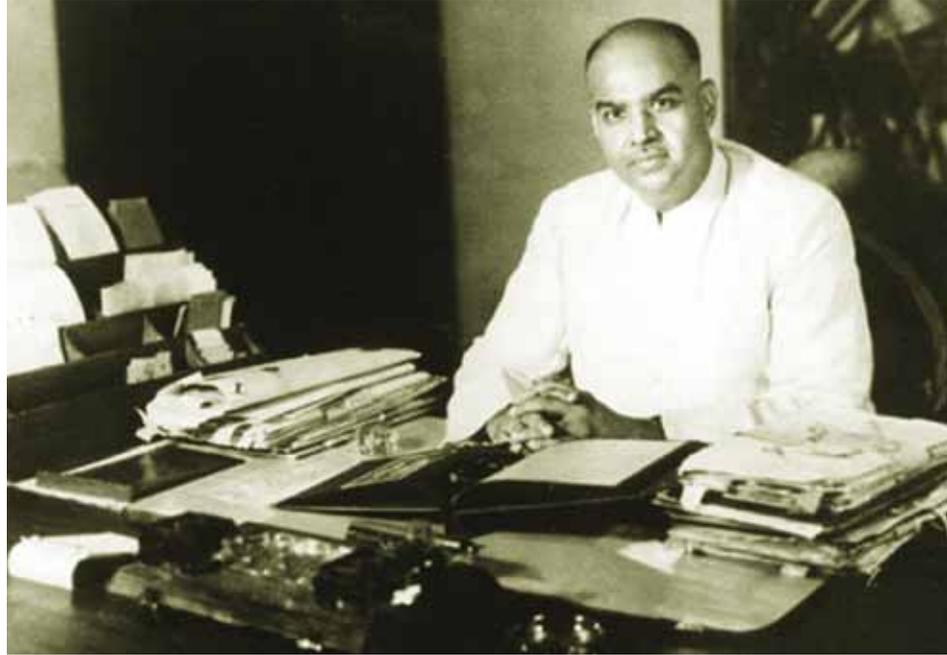
डॉ. मोहन यादव

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारतीय राजनीति और समाज में उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण और समय से आगे की सोच के लिए जाना जाता है। उनके जीवन और कार्यों ने दिखाया कि वे न केवल अपने समय के मुद्दों को समझते थे, बल्कि भविष्य की चुनौतियों और अवसरों का भी गहरा ज्ञान रखते थे।

देश और समाज के लिए तुष्टिकरण की राजनीति कितना नुकसान पहुंचा सकती है, इसको हमारे कई दार्शनिक समाजसेवियों ने दशकों पहले समझ लिया था। एक देश और एक विधान का मंत्र देने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके लिए मिसाल पेश की। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार ने तुष्टिकरण की नीति पर चलना शुरू किया तो डॉ. मुखर्जी ने कैबिनेट से इस्तीफा देकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की। आज केंद्र में भाजपा की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश की बागडोर है। इसके पीछे डॉ. मुखर्जी की ही नीति और सोच है।

आजादी मिलने के बाद बनी पहली केंद्र सरकार से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मतभेद देखने को मिले थे, जब तत्कालीन नेहरू सरकार ने भारत के संविधान में जबरन अनुच्छेद 370 जोड़कर देश की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया था। अखंड भारत के समर्थक डॉ. मुखर्जी ने कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति का विरोध किया।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत माता के महान सपूत थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल किया। नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच हुए समझौते के पश्चात 6 अप्रैल 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया।



आजादी मिलने के बाद बनी पहली केंद्र सरकार से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मतभेद देखने को मिले थे, जब तत्कालीन नेहरू सरकार ने भारत के संविधान में जबरन अनुच्छेद 370 जोड़कर देश की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया था। अखंड भारत के समर्थक डॉ. मुखर्जी ने कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति का विरोध किया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर-संघचालक गुरु गोलवलकर जी से परामर्श लेकर श्री मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना की। 1951-52 के आम चुनावों में राष्ट्रीय जनसंघ के तीन सांसद चुने गए जिनमें एक डॉ. मुखर्जी भी थे। तत्पश्चात उन्होंने संसद के अन्दर 32 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसदों के सहयोग से नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। डॉ. मुखर्जी भारत की अखंडता और कश्मीर के विलय के दृढ़ समर्थक थे।

उन्होंने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को भारत के बाल्कनीकरण की संज्ञा दी थी। अनुच्छेद 370 के राष्ट्रघातक प्रावधानों को हटाने के लिए भारतीय जनसंघ ने हिन्दू महासभा और रामराज्य परिषद के साथ सत्याग्रह आरंभ किया।

डॉ. मुखर्जी 11 मई 1953 को कुख्यात परमिट सिस्टम का उल्लंघन करके कश्मीर में प्रवेश करते हुए गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी के दौरान ही विषम परिस्थितियों में 23 जून, 1953 को उनका स्वर्गवास हो गया।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन और कार्य एक अद्वितीय उदाहरण है, जिसमें उन्होंने शिक्षा, राजनीति, और सामाजिक सुधार के विभिन्न मोर्चों पर उल्लेखनीय योगदान दिया। उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को एक प्रतिष्ठित बंगाली भद्रलोक परिवार में हुआ था, जो उस समय अपनी बौद्धिकता और सांस्कृतिक योगदान के लिए विख्यात था।

मात्र 33 साल की उम्र में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कोलकता विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। यह उनके ज्ञान, योग्यता और विद्वता का प्रमाण था। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने विश्वविद्यालय में शैक्षिक सुधार किए, नई पाठ्यक्रम नीतियों को लागू किया और छात्रों के समग्र विकास पर जोर दिया। डॉ. मुखर्जी ने हिंदू महासभा के माध्यम से हिंदू समाज के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए जोरदार वकालत की। उन्होंने बंगाल के विभाजन के समय हिंदू बहुल क्षेत्रों को भारत में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हमें गर्व है कि हम सब उसी जनसंघ से निकले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक प्रखर शिक्षाविद, दृढ़ राजनीतिज्ञ और निष्ठावान राष्ट्रवादी थे। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से भारतीय समाज और राजनीति में अमूल्य योगदान दिया। उनके द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ ने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, और उनके विचार आज भी भारतीय जनता पार्टी और अन्य राष्ट्रवादी संगठनों में प्रतिबिंबित होते हैं।

हमारे देश के लिए डॉ. मुखर्जी की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। हमें माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का संसद में दिया गया वह वक्तव्य पूरी तरह याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते, तो बंगाल भारत का हिस्सा नहीं होता। आज बंगाल अगर भारत में है तो डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण है। राष्ट्र सेवा में स्वयं को समर्पित करने वाले मां भारती के अमर सपूत एवं जनसंघ के संस्थापक श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्र हित में किये गए कार्य एवं उनका आदर्श व्यक्तित्व हम सभी के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगा।

राष्ट्र की अखंडता के लिए कंटकाकीर्ण मार्ग पर चलकर संगठन के एक-एक कार्यकर्ता को राष्ट्र प्रथम का मंत्र दिया। आज भाजपा के कार्यकर्ता वैभवशाली राष्ट्र निर्माण के लिए अहर्निश कार्य कर रहे हैं। डॉ. मुखर्जी की विचारधारा में देश की एकता-अखंडता, सांस्कृतिक उत्थान, देश के नागरिकों का आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक व राजनैतिक उत्थान समाहित है।

(लेखक मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं)

## प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव



### प्रधानमंत्री

श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन सत्र 2024-25 के लिए सभी आवश्यक खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी देने से किसानों को बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी और उनके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी की यह पहल जनकल्याण की भावना से किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली सिद्ध होगी। एमएसपी में इस वृद्धि से प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा अन्नदाताओं को दी गई पहली गारंटी पूर्ण होगी और देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एमएसपी में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार माना और किसानों को बधाई व शुभकामनाएं दी।

14 प्रकार की फसलों के मूल्यों में वृद्धि की गई है। समर्थन मूल्य पर की गई यह वृद्धि सिद्ध करती है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। धान का समर्थन मूल्य 2 हजार 300 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है, इसमें 117 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। अब कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7 हजार 521 रुपये होगा, यह पिछली दर से 501 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। इसी प्रकार उत्पादकों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तुअर, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, रामतिल आदि के न्यूनतम मूल्य में वृद्धि की गई है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी की मंशा किसानों की आय बढ़ाना है, उन्होंने हाल ही में किसान सम्मान निधि जारी कर किसानों की मदद की है। समर्थन मूल्य पर की गई वृद्धि से हार्डब्रिड ज्वार अब 3 हजार 371 रुपये, मालदंडी ज्वार 3 हजार 421 रुपये प्रति क्विंटल और बाजरा 2 हजार 625 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा जाएगा। रागी 4 हजार 290 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने के लिए दरों में 444 रुपये की वृद्धि की गई है। मक्का अब 2 हजार 225 रुपये प्रति क्विंटल खरीदी जाएगा। सोयाबीन में 292 रुपये की वृद्धि की गई है, अब यह 4 हजार 892 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा जाएगा। तिल की दर में 632 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, अब यह 9 हजार 267 रुपये प्रति क्विंटल की दर से लिया जाएगा।



# चर्चा संस्कृति, इतिहास और विकसित भारत की

वो दिन आ ही गया जिसका हम सभी फरवरी से इंतजार कर रहे थे। मैं 'मन की बात' के माध्यम से एक बार फिर आपके बीच, अपने परिवारजनों के बीच आया हूँ। एक बड़ी प्यारी सी उक्ति है - 'इति विदा पुनर्मिलनाय' इसका अर्थ भी उतना ही प्यारा है, मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलने के लिए। इसी भाव से मैंने फरवरी में आपसे कहा था कि चुनाव नतीजों के बाद फिर मिलूँगा, और 'मन की बात' के साथ, मैं, आपके बीच फिर हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और अब तो मानसून भी आ गया है, और जब मानसून आता है, तो मन भी आनंदित हो जाता है। फिर, एक बार, हम, 'मन की बात' में ऐसे देशवासियों की चर्चा करेंगे जो अपने कामों से समाज में, देश में, बदलाव ला रहे हैं। हम चर्चा करेंगे, हमारी, समृद्ध संस्कृति की, गौरवशाली इतिहास की, और, विकसित भारत के प्रयास की।

फरवरी से लेकर अब तक, जब भी, महीने का आखिरी रविवार आने को होता था, तब मुझे आपसे इस संवाद की बहुत कमी महसूस होती थी। लेकिन मुझे ये देखकर बहुत अच्छा भी लगा कि इन महीनों में आप लोगों ने मुझे लाखों संदेश भेजे। 'मन की बात' रेडियो प्रोग्राम भले ही कुछ महीने बंद रहा हो, लेकिन, 'मन की बात' का जो Spirit है देश में, समाज में, हर दिन अच्छे काम, निस्वार्थ भावना से किए गए काम, समाज पर positive असर डालने वाले काम - निरंतर चलते रहे। चुनाव की खबरों के बीच निश्चित रूप से मन को छू जाने वाली ऐसी खबरों पर आपका ध्यान गया होगा।

मैं देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है। 2024 का चुनाव, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। दुनिया के किसी भी देश में इतना बड़ा चुनाव कभी नहीं हुआ, जिसमें, 65 करोड़ लोगों ने वोट डाले



एक बड़ी प्यारी सी उक्ति है - "इति विदा पुनर्मिलनाय" इसका अर्थ भी उतना ही प्यारा है, मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलने के लिए। इसी भाव से मैंने फरवरी में आपसे कहा था कि चुनाव नतीजों के बाद फिर मिलूँगा, और "मन की बात" के साथ, मैं, आपके बीच फिर हाजिर हूँ।

उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और अब तो मानसून भी आ गया है, और जब मानसून आता है, तो मन भी आनंदित हो जाता है। फिर, एक बार, हम, "मन की बात" में ऐसे देशवासियों की चर्चा करेंगे जो अपने कामों से समाज में, देश में, बदलाव ला रहे हैं। हम चर्चा करेंगे, हमारी, समृद्ध संस्कृति की, गौरवशाली इतिहास की, और, विकसित भारत के प्रयास की।

हैं। मैं चुनाव आयोग और मतदान की प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति को इसके लिए बधाई देता हूँ।

30 जून का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन को हमारे आदिवासी भाई-बहन 'हूल दिवस' के रूप में मनाते हैं। यह दिन वीर सिद्धो-कान्हू के अदम्य साहस से जुड़ा है, जिन्होंने विदेशी शासकों के अत्याचार का

पुरजोर विरोध किया था। वीर सिद्धो-कान्हू ने हजारों संथाली साथियों को एकजुट करके अंग्रेजों का जी-जान से मुकाबला किया, और जानते हैं ये कब हुआ था? ये हुआ था 1855 में, यानी ये 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भी दो साल पहले हुआ था, तब, झारखंड के संथाल परगना में हमारे आदिवासी भाई-बहनों ने विदेशी



शासकों के खिलाफ हथियार उठा लिया था। हमारे संथाली भाई-बहनों पर अंग्रेजों ने बहुत सारे अत्याचार किए थे, उन पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए थे। इस संघर्ष में अद्भुत वीरता दिखाते हुए वीर सिद्धो और कान्हू शहीद हो गए। झारखंड की भूमि के इन अमर सपूतों का बलिदान आज भी देशवासियों को प्रेरित करता है।

अगर मैं आपसे पूछूँ कि दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता कौन सा होता है तो आप जरूर कहेंगे - 'माँ'। हम सबके जीवन में 'माँ' का दर्जा सबसे ऊँचा होता है। माँ, हर दुख सहकर भी अपने बच्चे का पालन-पोषण करती है। हर माँ, अपने बच्चे पर हर स्नेह लुटाती है। जन्मदात्री माँ का ये प्यार हम सब पर एक कर्ज की तरह होता है, जिसे कोई चुका नहीं सकता। मैं सोच रहा था, हम माँ को कुछ दे तो सकते नहीं, लेकिन, और कुछ कर सकते हैं क्या? इसी सोच में से इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है, इस अभियान का नाम है - 'एक पेड़ माँ के नाम'। मैंने भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी माँ के साथ मिलकर, या उनके नाम पर, एक पेड़ जरूर लगाएं। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि माँ की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग अपनी माँ के साथ या फिर उनकी फोटो के साथ पेड़ लगाने की तस्वीरों को Social Media पर साझा कर रहे हैं। हर कोई अपनी माँ के लिए पेड़ लगा रहा है - चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो कामकाजी महिला हो या गृहिणी। इस अभियान ने सबको माँ के प्रति अपना स्नेह जताने का समान अवसर दिया है। वो अपनी तस्वीरों को Planty Mother और 'एक पेड़ माँ के नाम' इसके साथ साझा करके दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। इस अभियान का एक और लाभ होगा। धरती भी माँ के समान हमारा ख्याल रखती है। धरती माँ ही हम सबके जीवन का आधार है, इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम धरती माँ का भी ख्याल रखें। माँ के नाम पेड़ लगाने के अभियान से अपनी माँ का सम्मान तो होगा ही होगा, धरती माँ की भी रक्षा होगी। पिछले एक दशक में भारत में सबके प्रयास से वन क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। अमृत महोत्सव के दौरान, देशभर में 60 हजार से ज्यादा अमृत सरोवर भी बनाए गए हैं। अब हमें ऐसे ही माँ के नाम पर पेड़

हम सबके जीवन में "माँ" का दर्जा सबसे ऊँचा होता है। माँ, हर दुख सहकर भी अपने बच्चे का पालन-पोषण करती है।

हर माँ, अपने बच्चे पर हर स्नेह लुटाती है। जन्मदात्री माँ का ये प्यार हम सब पर एक कर्ज की तरह होता है, जिसे कोई चुका नहीं सकता।

मैं सोच रहा था, हम माँ को कुछ दे तो सकते नहीं, लेकिन, और कुछ कर सकते हैं क्या? इसी सोच में से इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है, इस अभियान का नाम है - "एक पेड़ माँ के नाम"।

लगाने के अभियान को गति देनी है।

देश के अलग-अलग हिस्सों में मॉनसून तेजी से अपना रंग बिखेर रहा है। और बारिश के इस मौसम में सबके घर में जिस चीज की खोज शुरू हो गई है, वो है 'छाता'। 'मन की बात' में आज मैं आपको एक खास तरह के छातों के बारे में बताना चाहता हूँ। ये छाते तैयार होते हैं हमारे केरला में। वैसे तो केरला की संस्कृति में छातों का विशेष महत्व है। छाते, वहाँ कई परंपराओं और विधि-विधान का अहम हिस्सा होते हैं। लेकिन मैं जिस छाते की बात कर रहा हूँ, वो है 'कार्थुम्बी छाते' और इन्हें तैयार किया जाता है केरला के अट्टापडी में। ये रंग-बिरंगे छाते बहुत शानदार होते हैं। और खासियत ये इन छातों को केरला की हमारी आदिवासी बहनें तैयार करती हैं। आज देशभर में इन छातों की मांग बढ़ रही है। इनकी Online बिक्री भी हो रही है। इन छातों को 'वट्टालक्की सहकारी कृषि सोसाइटी' की देखरेख में बनाया जाता है। इस सोसाइटी का नेतृत्व हमारी नारी शक्ति के पास है। महिलाओं के नेतृत्व में अट्टापडी के आदिवासी समुदाय ने Entrepreneurship की अद्भुत मिसाल पेश की है। इस society ने एक बैबू-हैंडीक्राफ्ट यूनिट की भी स्थापना की है। अब ये लोग एक Retail outlet और एक पारंपरिक cafe खोलने की तैयारी में

एक पेड़ माँ

भी हैं। इनका मकसद सिर्फ अपने छाते और अन्य उत्पाद बेचना ही नहीं, बल्कि ये अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से भी दुनिया को परिचित करा रहे हैं। आज कार्थुम्बी छाते केरला के एक छोटे से गाँव से लेकर Multinational कंपनियों तक का सफर पूरा कर रहे हैं। लोकल के लिए वोक्ल होने का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या होगा?

अगले महीने इस समय तक Paris Olympic शुरू हो चुके होंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब भी Olympic खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का इंतजार कर रहे होंगे। मैं भारतीय दल को Olympic खेलों की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सबके मन में Tokyo Olympic की यादें अब भी ताजा हैं। Tokyo में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने हर भारतीय का दिल जीत लिया था। Tokyo Olympic के बाद से ही हमारे Athletes Paris Olympic की तैयारियों में जी-जान से जुटे हुए थे। सभी खिलाड़ियों को मिला दें, तो इन सबने करीब Nine Hundred-नौ सौ International competition में हिस्सा लिया है। ये काफी बड़ी संख्या है।

Paris Olympic में आपको कुछ चीजें पहली बार देखने को मिलेंगी। shooting में हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा निखरकर सामने आ रही है। Table-Tennis में Men और Women दोनों टीमों qualify कर चुकी हैं। भारतीय Shotgun Team में हमारी शूटर बेटियाँ भी शामिल हैं। इस बार कुश्ती और घुड़सवारी में हमारे दल



# माँ के नाम

के खिलाड़ी उन Categories में भी compete करेंगे, जिनमें पहले वे कभी शामिल नहीं रहे। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार हमें खेलों में अलग level का रोमांच नजर आएगा।

कुछ महीने पहले World Para Athletics Championship में हमारी Best Performance रही है। वहीं Chess और Badminton में भी हमारे खिलाड़ियों ने परचम लहराया है। अब पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि हमारे खिलाड़ी Olympics में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। इन खेलों में medals भी जीतेंगे, और देशवासियों का दिल भी जीतेंगे। आने वाले दिनों में, मुझे भारतीय दल से मुलाकात का अवसर भी मिलने वाला है। मैं आपकी तरफ से उनका उत्साहवर्धन करूंगा। और हाँ.. इस बार हमारा Hashtag #CheeryBharat है। इस Hashtag के जरिए हमें अपने खिलाड़ियों को cheer करना है... उनका उत्साह बढ़ाते रहना है। तो momentum को बनाए रखिए... आपका ये momentum... भारत का magic, दुनिया को दिखाने में मदद करेगा।

कुवैत रेडियो के एक प्रसारण की clip है। अब आप सोचेंगे कि बात हो रही है कुवैत की, तो वहाँ, हिन्दी कहाँ से आ गई? दरअसल, कुवैत सरकार ने अपने National Radio पर एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। और वो भी हिन्दी में। 'कुवैत रेडियो' पर हर रविवार को इसका प्रसारण आधे घंटे के लिए किया जाता है। इसमें भारतीय संस्कृति के अलग-अलग रंग

शामिल होते हैं। हमारी फिल्में और कला जगत से जुड़ी चर्चाएँ वहाँ भारतीय समुदाय के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। मुझे तो यहाँ तक बताया गया है कि कुवैत के स्थानीय लोग भी इसमें खूब दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं कुवैत की सरकार और वहाँ के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ये शानदार पहल की है।

दुनिया भर में हमारी संस्कृति का जिस तरह गौरवगान हो रहा है, उससे किस भारतीय को खुशी नहीं होगी! अब जैसे, तुर्कमेनिस्तान में इस साल मई में वहाँ के राष्ट्रीय कवि की 300वीं जन्म-जयंती मनाई गई। इस अवसर पर तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने दुनिया के 24 प्रसिद्ध कवियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इनमें से एक प्रतिमा गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी की भी है। ये गुरुदेव का सम्मान है, भारत का सम्मान है। इसी तरह जून के महीने में दो कैरेबियाई देश सूरीनाम और Saint Vincent and the Grenadines ने अपने Indian heritage को पूरे जोश और उत्साह के साथ celebrate किया। सूरीनाम में हिन्दुस्तानी समुदाय हर साल 5 जून को Indian Arrival Day और प्रवासी दिन के रूप में मनाता है। यहाँ तो हिन्दी के साथ ही भोजपुरी भी खूब बोली जाती है। Saint Vincent and the Grenadines में रहने वाले हमारे भारतीय मूल के भाई-बहनों की संख्या भी करीब छः हजार है। उन सबको अपनी विरासत पर बहुत गर्व है। एक जून को इन सबने Indian Arrival Day

को जिस धूम-धाम से मनाया, उससे उनकी ये भावना साफ झलकती है। दुनिया भर में भारतीय विरासत और संस्कृति का जब ऐसा विस्तार दिखता है तो हर भारतीय को गर्व होता है।

इस महीने पूरी दुनिया ने 10वें योग दिवस को भरपूर उत्साह और उमंग के साथ मनाया है। मैं भी जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुआ था। कश्मीर में युवाओं के साथ-साथ बहनों-बेटियों ने भी योग दिवस में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। जैसे-जैसे योग दिवस का आयोजन आगे बढ़ रहा है, नए-नए records बन रहे हैं। दुनिया-भर में योग दिवस ने कई शानदार उपलब्धियाँ हासिल की हैं।

सऊदी अरब में पहली बार एक महिला अल हनौफ साद जी ने common yoga protocol को lead किया। ये पहली बार है जब किसी सऊदी महिला ने किसी main yoga session को instruct किया हो। Egypt में इस बार योग दिवस पर एक photo competition का आयोजन किया गया। नील नदी के किनारे Red Sea के beaches पर और पिरामिडों के सामने - योग करते, लाखों लोगों की तस्वीरें बहुत लोकप्रिय हुईं। अपने Marble Buddha Statue के लिए प्रसिद्ध Myanmar का माराविजया पैगोडा कॉम्प्लेक्स दुनिया में मशहूर है। यहाँ भी 21 जून को शानदार Yoga Session का आयोजन हुआ। बहरीन में दिव्यांग बच्चों के लिए एक





Special Camp का आयोजन किया गया। श्रीलंका में UNESCO heritage site के लिए मशहूर गॉल फोर्ट में भी एक यादगार Yoga Session हुआ। अमेरिका के New York में Observation Deck पर भी लोगों ने योग किया। Marshal Islands पर भी पहली बार बड़े स्तर पर हुए योग दिवस के कार्यक्रम में यहाँ के राष्ट्रपति जी ने भी हिस्सा लिया। भूटान के थिंपू में भी एक बड़ा योग दिवस का कार्यक्रम हुआ, जिसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री टोबो भी शामिल हुए। यानी दुनिया के कोने-कोने में योग करते लोगों के विहंगम दृश्य हम सबने देखे। मैं योग दिवस में हिस्सा लेने वाले सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा आपसे एक पुराना आग्रह भी रहा है। हमें योग को केवल एक दिन का अभ्यास नहीं बनाना है। आप नियमित रूप से योग करें। इससे आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों को जरूर महसूस करेंगे।

भारत के कितने ही products हैं जिनकी दुनिया-भर में बहुत demand है और जब हम भारत के किसी local product को global होते देखते हैं, तो गर्व से भर जाना स्वाभाविक है।

ऐसा ही एक product है Araku coffee. Araku coffee आंध्र प्रदेश के अल्लुरी सीता राम राजू जिले में बड़ी मात्रा में पैदा होती है। ये अपने rich flavor और aroma के लिए जानी जाती है। Araku coffee की खेती से करीब डेढ़ लाख आदिवासी परिवार जुड़े हुए हैं। Araku coffee को नई ऊँचाई देने में Girijan cooperative की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसने यहाँ के किसान भाई बहनों को एक साथ लाने का काम किया और

उन्हें Araku coffee की खेती के लिए प्रोत्साहन दिया। इससे इन किसानों की कमाई भी बहुत बढ़ गई है। इसका बहुत लाभ कोंडा डोरा आदिवासी समुदाय को भी मिला है। कमाई के साथ साथ उन्हें सम्मान का जीवन भी मिल रहा है। मुझे याद है एक बार विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गारु के साथ मुझे इस coffee का स्वाद लेने का मौका मिला था। इसके taste की तो पूछिए ही मत! कमाल की होती है ये coffee! Araku coffee को कई Global awards मिले हैं। दिल्ली में हुई G-20 समिट में भी coffee छाई हुई थी। आपको जब भी अवसर मिले, आप भी Araku coffee आनंद जरूर लें।

Local products को Global बनाने में हमारे जम्मू-कश्मीर के लोग भी पीछे नहीं हैं। पिछले महीने जम्मू-कश्मीर ने जो कर दिखाया है, वो देश भर के लोगों के लिए भी एक मिसाल है। यहाँ के पुलवामा से snow peas की पहली खेप लंदन भेजी गई। कुछ लोगों को ये idea सूझा कि कश्मीर में उगने वाली exotic vegetables को क्यों ना दुनिया के नक्शे पर लाया जाए। बस फिर क्या था, चकूरा गांव के अब्दुल राशीद मीर जी इसके लिए सबसे पहले आगे आए। उन्होंने गांव के अन्य किसानों की जमीन को एक साथ मिलाकर snow peas उगाने का काम शुरू किया और देखते ही देखते snow peas कश्मीर से लंदन तक पहुँचने लगी। इस सफलता ने जम्मू-कश्मीर के लोगों की समृद्धि के लिए नए द्वार खोले हैं। हमारे देश में ऐसे unique products की कमी नहीं है। आप ऐसे products को #myproductsmypride के साथ जरूर share करें। मैं इस विषय पर आने वाले

‘मन की बात’ में भी चर्चा करूँगा।

**मम प्रिया: देशवासिनः  
अद्य अहं किञ्चित् चर्चा संस्कृत  
भाषायां आरंभे।**

आप सोच रहे होंगे कि ‘मन की बात’ में अचानक संस्कृत में क्यों बोल रहा हूँ? इसकी वजह है, आज संस्कृत से जुड़ा एक खास अवसर! आज 30 जून को आकाशवाणी का संस्कृत बुलेटिन अपने प्रसारण के 50 साल पूरे कर रहा है। 50 वर्षों से लगातार इस बुलेटिन ने कितने ही लोगों को संस्कृत से जोड़े रखा है। मैं All India Radio परिवार को बधाई देता हूँ।

संस्कृत की प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान की प्रगति में बड़ी भूमिका रही है। आज के समय की मांग है कि हम संस्कृत को सम्मान भी दें, और उसे अपने दैनिक जीवन से भी जोड़ें। आजकल ऐसा ही एक प्रयास बेंगलुरु में कई और लोग कर रहे हैं। बेंगलुरु में एक पार्क है- कब्बन पार्क! इस पार्क में यहाँ के लोगों ने एक नई परंपरा शुरू की है। यहाँ हफ्ते में एक दिन, हर रविवार बच्चे, युवा और बुजुर्ग आपस में संस्कृत में बात करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ वाद-विवाद के कई session भी संस्कृत में ही आयोजित किए जाते हैं। इनकी इस पहल का नाम है - संस्कृत weekend! इसकी शुरुआत एक website के जरिए समष्टि गुब्बी जी ने की है। कुछ दिनों पहले ही शुरू हुआ ये प्रयास बेंगलुरु वासियों के बीच देखते ही देखते काफी लोकप्रिय हो गया है। अगर हम सब इस तरह के प्रयास से जुड़ें तो हमें विश्व की इतनी प्राचीन और वैज्ञानिक भाषा से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।

‘मन की बात’ के इस episode में आपसे जुड़ना बहुत अच्छा रहा। अब ये सिलसिला फिर पहले की तरह चलता रहेगा। अब से एक सप्ताह बाद पवित्र रथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। मेरी कामना है कि महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा सभी देशवासियों पर सदैव बनी रहे। अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है, और अगले कुछ दिनों में पंढरपुर वारी भी शुरू होने वाली है।

मैं इन यात्राओं में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूँ। आगे कच्ची नववर्ष - आषाढी बीज का त्योहार भी है। इन सभी पर्व-त्योहारों के लिए भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि Positivity से जुड़े जनभागीदारी के ऐसे प्रयासों को आप मेरे साथ अवश्य Share करते रहेंगे। मैं अगले महीने आपके साथ फिर से जुड़ने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ■

# सुशासन के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज



शिवप्रकाश

**राष्ट्रीय** जनतान्त्रिक गठबंधन की जीत के उपलक्ष्य में आयोजित “धन्यवाद भारत कार्यक्रम” के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को स्मरण करते हुए कहा कि “कुछ ही दिनों में देश छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्यारोहण की 350 वीं वर्षगांठ मनाएगा, उनका जीवन ध्येय पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देता है”। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत् 1731 को रायगढ़ में हुआ था। पुर्तगाली एवं ब्रिटिशों सहित अनेकों विदेशी लेखकों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना विश्व के महानतम सेनापति नेपोलियन, सीजर, सिकन्दर के साथ करते हुए उनकी वीरता, साहस, प्रशासनिक कुशलता एवं युद्ध शैली की प्रशंसा की है।

16 फरवरी 1630 ईस्वी को शिवनेरी किले में शिवाजी महाराज का जन्म शाहजी भोंसले एवं माता जीजाबाई के परिवार में हुआ। उनके जन्म के समय परिस्थितियाँ कैसी थी इसका वर्णन समर्थ गुरु रामदास महाराज ने अपने 12 वर्ष के भारत भ्रमण के पश्चात् इस प्रकार किया “या भूमंडलाचे ढायी, धर्मरक्षा ऐसा नाही” इस समय इस भूमंडल पर धर्मरक्षक कोई नहीं है। सम्पूर्ण देश में कोई भी मंदिर सुरक्षित नहीं है सामान्य जनता मुगलों के अत्याचार से कराह रही है, किसी भी नदी का जल पवित्र नहीं है जिससे अभिषेक किया जा सके। इस विकट परिस्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने रणकौशल एवं बुद्धिकौशल से स्वराज की स्थापना की। उनके कुशल प्रशासन को देखने के बाद पुनः स्वयं समर्थ रामदास महाराज ने कहा कि “आचारशील, विचारशील, न्यायशील, धर्मशील, सर्वज्ञ सुशील जाणता राजा” (जाणता अर्थात्



**शिवाजी महाराज ने सहयाद्री में निवास करने वाले सामान्य गरीब, किसान, युवकों में स्वराज की प्रेरणा जगायी। समाज के सामान्य वर्ग से निकले इन्हीं योद्धाओं ने अपने जीवन की बाजी लगाकर स्वराज स्थापना का श्रेष्ठतम कार्य किया।**

औरंगजेब अपनी सेना के एक-एक सेनापति से तुलना करते हुए शिवाजी महाराज के सेनापतियों की विशेषता का वर्णन करते हुए कहता है कि “वे झुकते नहीं, रुकते नहीं, थकते नहीं और बिकते भी नहीं”।

सदैव जागरूक)।

किसी भी कार्य की सफलता का आधार नेतृत्वकर्ता के सहयोगी कैसे हैं, इस पर निर्भर करता है। शिवाजी महाराज ने सहयाद्री में निवास करने वाले सामान्य गरीब, किसान, युवकों में स्वराज की प्रेरणा जगायी। समाज के सामान्य वर्ग से निकले इन्हीं योद्धाओं ने अपने जीवन की बाजी लगाकर स्वराज स्थापना का श्रेष्ठतम कार्य किया। औरंगजेब अपनी सेना के एक-एक सेनापति से तुलना करते हुए शिवाजी महाराज के सेनापतियों की

विशेषता का वर्णन करते हुए कहता है कि “वे झुकते नहीं, रुकते नहीं, थकते नहीं और बिकते भी नहीं”।

छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन लोक कल्याण एव पारदर्शिता से युक्त था। अपने वित्त प्रबंधन को लेकर वे सदैव सजग थे। अपने मंत्रालयों की समीक्षा करते समय उन्होंने अपने लेखपाल से पूछ लिया कि कल तक का हिसाब दैनंदनी में चढ़ा अथवा नहीं, नकारात्मक उत्तर होने पर लापरवाही के लिए कठोर दंड भी दिया। लगान के

उचित संग्रह में लापरवाही पर देश कुलकर्णी आपाजी से जुर्माना भी लिया एवं पद मुक्त भी किया। भ्रष्टाचार विहीन शासन छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन का वैशिष्ट्य था। भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए उन्होंने रिश्वत लेने पर अपने सौतेले मामा मोहिते को भी कारागार में डाल दिया था। 13 मई 1671 के अपने पत्र में वे लिखते हैं कि अगर आप जनता को तकलीफ देंगे, कार्य सम्पादन में रिश्वत मांगेंगे तो जनता को लगेगा कि इससे तो मुगलों का शासन ही अच्छा था।

छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज संचालन के लिए अष्ट प्रधान शासन प्रणाली की व्यवस्था दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज जहाँ एक दूरदर्शी योद्धा थे, वहीं वह एक कुशल प्रशासक भी थे।

स्वदेशी जलपोत निर्माण के लिए मुंबई के पास कल्याण एवं भिवंडी में उनके द्वारा स्थापित जलपोत निर्माण कारखाना, व्यापार एवं सुरक्षा के प्रति उनकी दृष्टि की ओर इंगित करता है। अंग्रेजों से तोप निर्माण की तकनीक न मिलने पर उन्होंने फ्रांस के सहयोग से पुरन्दर किले पर तोपखाना स्थापित कराया। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का यह मन्त्र वर्तमान की सरकार का मन्त्र भी बना है।

भूमि का मापन, पैदावार का मूल्यांकन, आपदा में होने वाली हानि के मूल्यांकन की व्यवस्था शिवाजी महाराज ने उस समय की थी। सिंचाई के लिए बाँध, तालाबों, कुएँ, बावड़ी एवं जलाशयों का निर्माण उनकी दूरदर्शिता को प्रकट करते हैं। स्वस्थ भूमि, स्वस्थ उत्पाद, स्वस्थ पर्यावरण के लिए फसलों में विविधता, फलदार वृक्षों को लगवाना उनकी कृषि एवं पर्यावरण के प्रति दृष्टि को प्रकट करते हैं।

महिलाओं के प्रति उनके हृदय में सम्मान एवं महिलाओं पर कुदृष्टि डालने पर कठोर दंड उनके शासन की व्यवस्था थी। मुस्लिम महिला गोहरबानू के प्रति उनके उद्गार काश मेरी माँ भी इतनी सुन्दर होती, सखोजी गायकवाड़ को दंड उनकी न्यायप्रियता को प्रकट करते हैं। स्वराज के हित को प्रथम रखते हुए उन्होंने व्यापारिक सम्बन्ध सभी से रखे थे। व्यापार के लिए मध्य एशिया के देशों तक उन्होंने सम्बन्ध बनाये थे। उनमें मस्कट के इमाम भी प्रमुख थे। उन्होंने अन्धविश्वास एवं कुरीतियों को तोड़ते हुए वैज्ञानिक दृष्टि को अपने राज्य संचालन का आधार बनाया। उनके शासन में वृद्ध, बीमार एवं बच्चों को छोड़कर अन्य किसी के लिए भी मुफ्त सुविधा की व्यवस्था नहीं थी।

छत्रपति शिवाजी महाराज की शासन

प्रणाली में स्वभाषा एवं स्वसंस्कृति को विशेष महत्व था। गुलामी के प्रतीकों को हटाकर स्वाभिमानी समाज जागृत करने के लिए उन्होंने किलों के नामों का नामांतरण भी किया। उर्दू और फारसी के शब्द बदलकर स्वराज संचालन के लिए 1400 हिन्दी शब्दों का कोष भी बनाया था।

छत्रपति शिवाजी महाराज की गुप्तचर व्यवस्था, शत्रु को पहचानने की उनकी अचूक दृष्टि उनको शेष भारतीय राजा-महाराजाओं से अलग करती है। उत्तर भारत की मुगल शक्ति एवं दक्षिण की आदिलशाही, कुतुबशाही के भेद का उन्होंने उचित उपयोग किया था। अंग्रेज व्यापारी स्वभाव के हैं, उन्होंने इसको अच्छे से पहचान कर उसी दृष्टि से उनके साथ व्यवहार भी किया था। शत्रु के साथ “जैसे को तैसा व्यवहार” (शठे शाठयम समाचरेत) शाइस्ताखान, अफजलखान एवं औरंगजेब से युद्ध करते समय उन्होंने अपनाया था। व्यापार एवं सुरक्षा के लिए नौसेना के महत्व को पहचान कर सिंधु दुर्ग सहित समुद्र किनारे अनेक दुर्गों की स्थापना उन्होंने की थी। अपने धर्म से विमुख हुए लोगों को अपने धर्म में पुनः वापसी भी उन्होंने करायी थी।

छत्रपति शिवाजी महाराज ने न केवल हिन्दवी साम्राज्य स्थापित किया, बल्कि सम्पूर्ण समाज में स्वराज, स्वधर्म के प्रति समर्पण की भावना भी जागृत की। देश भर में स्वराज की रक्षा के लिए संघर्षरत समस्त राजा-महाराजाओं के प्रेरणा पुंज भी वह बने। बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल, असम के लाचिद बड़फूकन उन्हीं से प्रेरणा लेकर संघर्ष कर रहे थे। विजय प्राप्ति पर अहोम राजाओं ने कहा कि हमारी प्रेरणा का केंद्र शिवाजी हैं।

अपनी माता की मृत्यु के समय भी बिना अवकाश लिए वे राज्य का सूत्र संचालन करते रहे, और न ही कोई शासकीय अवकाश घोषित किया। स्वराज संस्थापन के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करना ही उनकी प्रेरणा थी। स्वराज स्थापन यह “श्री” का कार्य है यह मान कर उन्होंने सम्पूर्ण जीवन भर संघर्ष किया। अपने सहयोगियों में भी उन्होंने यही भाव कूट-कूट कर भरा था।

सहयोगियों से वे कहते थे कि हमारे कार्य की दिशा ठीक है यह पवित्र कार्य है। हमारा कार्य पवित्र होने के कारण पवित्र अदृश्य शक्तियाँ हमारा सहयोग करेंगी। माँ तुलजा भवानी एवं परमेश्वर पर यह आस्था ही उनके संघर्ष की प्रेरणा थी। निमित्तता के इसी निस्वार्थ भाव के कारण उन्होंने एक कागज पर लिखकर अपना राज्य अपने प्रेरणा स्रोत

समर्थ रामदास स्वामी महाराज की छोली में डाल दिया था।

हिन्दवी स्वराज्य की स्थापना के इस पुनीत अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन आदर्श से प्रेरणा लेकर अपने देश को आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से सम्पन्न, सुरक्षित एवं सांस्कृतिक मूल्यों से संरक्षित कर विश्व वन्दनीय भारत बनाएं। ■

(लेखक-भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं)

## जीत परिश्रम व त्याग से मिली हितानंद जी



जीत के रास्ते पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में हमने 27 सीटें जीती थीं, 2019 के चुनाव में 28 जीतों और 2024 के चुनाव में हमने सभी 29 सीटों पर जीत हासिल की है। पार्टी कार्यकर्ताओं के परिश्रम तथा पूर्वजों के त्याग से हम हर चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। 1984 के लोकसभा चुनाव में मध्यप्रदेश में हमें 30 प्रतिशत वोट मिले थे, वहीं, हालिया चुनाव में हमारा वोट शेयर 60 प्रतिशत से अधिक रहा है।

# रानी दुर्गावती - जनकल्याण और शौर्य का शिखर



डॉ. मोहन यादव

**दुर्गाष्टमी** का दिन था जब भारत भूमि पर एक ऐसी बेटी ने जन्म लिया, जिसके संस्कारों में एक तरफ तो करुणा और संवेदना समाहित थी, वहीं दूसरी ओर शौर्य, पराक्रम और सतीत्व रगों में दौड़ता था। आज पांच सौ वर्षों के बाद भी हम यदि इतनी श्रद्धा और गौरव के साथ वीरंगना रानी दुर्गावती का स्मरण कर रहे हैं तो वह किसी राज परिवार की प्रमुख होने के नाते नहीं, बल्कि उनके दूरगामी जनकल्याणकारी कार्यों और शौर्य की उस गाथा के कारण कर रहे हैं, जिसने भारत की नारी की वीरता को शिखरतम बिन्दु तक रेखांकित किया है। 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर में पैदा हुई दुर्गावती का बलिदान 24 जून 1564 में हुआ। अर्थात् 40 वर्ष की आयु में उन्होंने एक ऐसी प्रेरक परिपाटी खड़ी कर दी, जो आज भी मानवता के लिए मिसाल बनी हुई है। महारानी की वीरता की बात करें तो उन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में लगभग 52 युद्ध लड़े और उनमें से 51 युद्धों में विजय प्राप्त हुई। मालवा के सुल्तान बाज बहादुर से लेकर अकबर तक मुगलों के अनेक भारी आक्रमणों का मुंहतोड़ जवाब देने वाली दुर्गावती ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आत्म बलिदान दिया। कोई दुश्मन उनकी देह को हाथ नहीं लगा सका। क्या अद्भुत अवतारी थीं, रानी दुर्गावती के विवाह के मात्र चार वर्ष बाद ही पति दलपत शाह की मृत्यु के कारण पूरे राजकाज का बोझ सिर पर आने के बाद भी न केवल एक वर्ष के अपने बेटे की परवरिश की बल्कि निरंतर युद्ध के मैदान में भी वीरता दिखाई।

सोलह वर्ष के शासन काल में एक ओर जहां दुर्गावती लगभग 52 बड़े युद्धों में रणचण्डी की तरह टूटती रहीं, वहीं दूसरी ओर राज्य की जनता की खुशहाली के लिए पूरी संवेदनाओं के साथ सक्रिय रहीं। जल संरक्षण के क्षेत्र में रानी दुर्गावती के योगदान को वैश्विक मानकों

शौर्य या वीरता रानी दुर्गावती के व्यक्तित्व का एक पहलू था। वो एक कुशल योद्धा होने के साथ-साथ एक कुशल प्रशासक थीं और उनकी छवि एक ऐसी रानी के रूप में भी थी, जो प्रजा के कष्टों को पूरी गहराई से अनुभव करती थीं।

में सबसे ऊपर रखा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपने सहयोगियों के प्रति ऐसा असीम स्नेह करती थीं कि उनके नाम पर कई बांध, तालाब और बाबड़ियां बनाईं। अपने सहयोगी के नाम पर निर्मित आधारताल आज भी जबलपुर में रानी के जल संरक्षण के उच्च मानकों की गाथा गौरव के साथ कह रहा है।

शौर्य या वीरता रानी दुर्गावती के व्यक्तित्व का एक पहलू था। वो एक कुशल योद्धा होने के साथ-साथ एक कुशल प्रशासक थीं और उनकी छवि एक ऐसी रानी के रूप में भी थी, जो प्रजा के कष्टों को पूरी गहराई से अनुभव करती थीं। इसीलिए गोंडवाना क्षेत्र में उन्हें उनकी वीरता और अदम्य साहस के अलावा उनके जनकल्याणकारी शासन के लिए भी याद किया जाता है। रानी दुर्गावती के शासन में नारी की सुरक्षा और सम्मान उत्कर्ष पर था। न्याय और समाज व्यवस्था के लिए हजारों गांवों में रानी के प्रतिनिधि रहते थे। प्रजा की बात रानी स्वयं सुनती थीं। पूरा कोइतूर गोंड समाज उनके निष्पक्ष न्याय के लिए उन्हें “न्याय की देवी” के नाम से पुकारता और जानता था। रानी दुर्गावती अपने पराजित दुश्मन के साथ भी उदारता का व्यवहार करती थीं और उन्हें सम्मानपूर्वक कीमती उपहार और पुरस्कार के साथ शुभकामनाएँ देकर अपने नियंत्रण में रखती थीं। उनकी यह रणनीति हमेशा काम करती थी इसीलिए कभी भी गोंडवाना में विद्रोह के स्वर नहीं उठे।

वे जन कल्याण की जीवंत प्रतिमूर्ति थीं। गोंड साम्राज्य में बने तमाम मठ मंदिर, कुंए, तालाब, नहरें, धर्मशालाएँ इसकी गवाह हैं। उनके साम्राज्य में समृद्धि ऐसी थी कि जनता स्वर्ण मुद्राओं से व्यापार करती थी। इसी समृद्धि को लूटने के लिए अकबर जैसे आक्रांताओं ने दुर्गावती के राज्य पर बार-बार आक्रमण किए। रानी ने बार-बार अकबर को शिकस्त दी, लेकिन अकबर की सेना के साथ चौथे युद्ध में वे बुरी तरह घिर गईं। उनकी आंख और गर्दन में तीर घुस गए तब उन्होंने अपने संकल्प “विजय नहीं तो क्या हुआ, बलिदान तो संभव है” का स्मरण करते हुए स्वयं के वक्ष में कटार घोंपकर रणभूमि में आत्म बलिदान कर दिया। रानी की चिता को रणभूमि में ही अग्नि दी गई। उसी स्थान को बरेला नाम से जानते हैं।

सच तो यह है कि आत्म अस्मिता और स्वतंत्रता के लिए दिए जाने वाले ऐसे बलिदान ही प्रतिमान गढ़ते हैं। लेकिन यह प्रतिमान प्रतिपल ध्यान में रहें तो पीढ़ियों तक राष्ट्र स्वाभिमान जाग्रत रह सकता है। दुर्भाग्य से 1947 की स्वतंत्रता के बाद भी लंबे समय तक रानी दुर्गावती जैसी वीरांगनाओं और शूरवीरों की स्मृतियों को संजोए रखने के बेहतर प्रयास नहीं

हुए। मुगलों, शकों, हूणों और अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए युद्धों की श्रृंखला में हमारे वनवासी, जनजाति समाज के नायकों का अतुलनीय और अविस्मरणीय योगदान है। परन्तु सच तो यही है कि रानी दुर्गावती से लेकर महानायक बिरसा मुण्डा, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, टंट्या मामा जैसे महानायकों के शौर्य की प्राण प्रतिष्ठा का काम हमारे विचार की सरकारों ने ही किया है। भारत में जहां “जनजातीय गौरव दिवस” जैसा आत्म-सम्मान प्रदान करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का संकल्प हो अथवा जनजाति मंत्रालय के पृथक गठन का पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का ऐतिहासिक फैसला हो, राष्ट्रीय विचार ने ही अपने उन भाई-बहनों के सम्मान और संसाधन पर ध्यान केन्द्रित किया है, जो कभी राजा थे लेकिन समय के थपड़े में बिछड़ते और पिछड़ते चले गए।

जनजाति समाज की समृद्ध परंपराओं पर केन्द्रित करते हुए हमारी सरकारों ने अपने बंधुओं को सम्मान और संसाधन से परिपूर्ण बनाने के लिए ‘पेसा’ एक्ट लागू किया। महानायकों की स्मृतियों को चिरस्थायी रखने के लिए

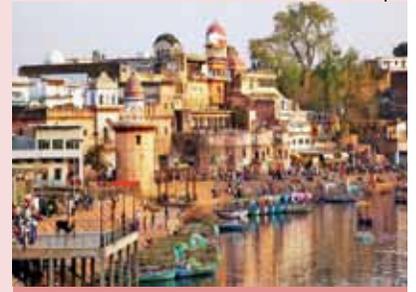
जहां संग्रहालय बनाए जा रहे हैं, वहीं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की पहल पर भोपाल में रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति को समर्पित कर दिया गया है। जनजाति महानायकों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है। सरकार की पहली कैबिनेट बैठक रानी दुर्गावती की सुशासन नगरी जबलपुर में किए जाने का हमारा भावनात्मक आधार ही था। यह रानी दुर्गावती का 500वां जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। हम इसे दूरगामी प्रेरणा पर्व के रूप में मनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का भरपूर लाभ जनजाति समाज को मिले, ऐसा भरसक प्रयास हम कर रहे हैं। जनजाति अस्मिता, संरक्षण और सांस्कृतिक संवर्धन हमारी सरकार का संकल्प है। जनजाति समाज को सम्मान और संसाधन प्रदान करना हमारा नैतिक दायित्व है। यही रानी दुर्गावती जैसी शौर्य, पराक्रम और संवेदनशीलता की प्रतिमूर्ति के श्रीचरणों में सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

(लेखक मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं)

## तीर्थ स्थल विकसित करेंगे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

**मध्यप्रदेश** भाजपा सरकार भगवान श्रीराम वनगमन पथ तथा श्रीकृष्ण पाथेय अर्थात् भगवान श्रीराम ने मध्यप्रदेश के जिन-जिन स्थानों से यात्रा की है उन स्थानों को चिन्हित कर तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करेंगे। मध्यप्रदेश सरकार चित्रकूट के आवागमन का मार्ग या लंका विजय के पश्चात पुनः अयोध्या प्रयाण का जो मार्ग है उस मार्ग को चिह्नित करते हुए तीर्थ के रूप में विकसित करने जा रही है।



भगवान श्रीराम ने जहां 11 वर्ष चित्रकूट धाम में व्यतीत किए हैं। उस स्थान पर समेकित रूप से एकीकृत योजना बनाते हुए चित्रकूट धाम पर भव्य पैमाने पर भगवान श्रीराम का काल स्मरणीय और दर्शनीय हो इसके लिए कार्य प्रारंभ किया है।

भगवान श्रीराम के गौरवशाली अतीत से प्रदेश का गहरा रिश्ता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान श्रीराम ने मंदाकिनी के किनारे मध्यप्रदेश में लंबा समय गुजारा है। भगवान श्रीराम के सभी भक्तों और श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आइये अयोध्या धाम के साथ चित्रकूट धाम के भी दर्शन करें। सांस्कृतिक रूप से रिश्तों को प्रगाढ़ करें।

भगवान श्रीकृष्ण की मध्यप्रदेश में यात्राओं से संबंधित स्थल जैसे उज्जैन में भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा, जानापाव में भगवान परशुराम जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान करने तथा धार के पास अमझीरा में रूक्मिणी जी के हरण के पवित्र स्थानों को तीर्थ स्थल बनाने जा रही है। हमारे आराध्य भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े लीला स्थलों को चिन्हित करते हुए तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करेंगे।

27 फरवरी, 1931 के दिन चन्द्रशेखर आजाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ बैठकर विचार-विमर्श कर रहे थे कि तभी वहां अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। चन्द्रशेखर आजाद ने सुखदेव को तो भगा दिया पर खुद अंग्रेजों का अकेले ही सामना करते रहे, अंत में जब अंग्रेजों की एक गोली उनकी जांघ में लगी तो अपनी बंदूक में बची एक गोली को उन्होंने खुद ही मार ली और अंग्रेजों के हाथों मरने की बजाय खुद ही को ही समाप्त कर लिया।

# अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद



**भा** रतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश के कई क्रांतिकारी वीर-सपूतों की याद आज भी हमारी रूह में जोश और देशप्रेम की एक लहर पैदा कर देती है एक वह समय था जब लोग अपना सब कुछ छोड़कर देश को आजाद कराने के लिए बलिदान देने को तैयार रहते थे। देशभक्ति की जो मिसाल हमारे देश के क्रांतिकारियों ने पैदा की थी उसी का परिणाम है कि आज हम सुख चैन से स्वतंत्र देश के नागरिक के रूप में आजाद हैं। वीरता और पराक्रम की कहानी हमारे देश के वीर क्रांतिकारियों ने रखी थी वह आजादी की लड़ाई की विशेष कड़ी थी, जिसके बिना आजादी मिलना नामुमकिन थी। देशप्रेम, वीरता और साहस की एक ऐसी ही मिसाल थी। शहीद क्रांतिकारी चन्द्रशेखर आजाद, 25 साल की उम्र में भारत माता के लिए शहीद होने वाले योद्धा थे। इस महापुरुष के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आजाद प्रखर देशभक्त थे।

चन्द्रशेखर आजाद का जन्म मध्यप्रदेश के जिला अलीराजपुर ग्राम भाबरा में 23 जुलाई सन् 1906 को हुआ। आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी संवत् 1956 में अकाल के समय अपने पैतृक निवास बदरका, वर्तमान उन्नाव जिला, उत्तरप्रदेश को छोड़कर कुछ दिनों मध्य प्रदेश अलीराजपुर रियासत में नौकरी करते रहे, फिर जाकर भाबरा गाँव में बस गये। उनकी माँ का नाम जगरानी देवी था। आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भाबरा गाँव में बीता। अतएव बचपन में आजाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाये। यहीं बालक चन्द्रशेखर का बचपन बीता। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। बालक चन्द्रशेखर आजाद का

मन अब देश को आजाद कराने के अहिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रान्ति की ओर मुड़ गया। उस समय बनारस क्रान्तिकारियों का गढ़ था। वह मन्मथनाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के सपर्क में आये और क्रान्तिकारी दल के सदस्य बन गये। क्रान्तिकारियों का वह दल हिन्दुस्तान प्रजातन्त्र संघर्ष के नाम से जाना जाता था।

असहयोग आंदोलन से जागे देश में दमनचक्र जारी था, सत्याग्रहियों के बीच निकल पड़े, प्रस्तरखंड उठाया बेंत बरसाने वालों में से एक सिपाही के सिर में दे मारा, पेशी होने पर अपना नाम आजाद, काम आजादी के कारखाने में मजदूरी और निवास जेलखाने में बताया। गुम्साए अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने पंद्रह बेंतों की सख्त सजा सुनाई, हर सांस में वंदेमातरम का निनाद करते हुए उन्होंने यह परीक्षा भी उत्तीर्ण की।

## क्रांतिकारी चन्द्रशेखर आजाद

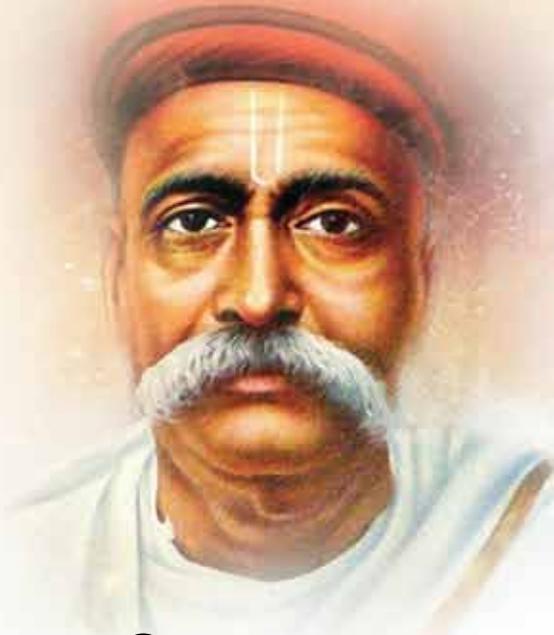
अचूक निशानेबाज आजाद ने अपना पावन शरीर मातृभूमि के शत्रुओं को फिर कभी छूने नहीं दिया। क्रांति की जितनी योजनाएँ बनीं सभी के सूत्रधार आजाद थे, कानपुर में भगत सिंह से भेंट हुई, साथियों के अनुरोध पर आजाद एक रात घर गए और सुषुप्त माँ एवं जागते पिता को प्रणाम कर कर्तव्य पथ पर वापस आ गए। सांडर्स का वर्धाविधान पूरा कर राजगुरु, भगतसिंह और आजाद फरार हो गए, 8 अप्रैल 1929 को श्रमिक विरोधी ट्रेड डिस्प्यूट बिल का परिणाम सभापति द्वारा खोलते ही इसके लिए नियुक्त दर्शक दीर्घा में खड़े दत्त और भगत सिंह को असेंबली में बम के धमाके के साथ इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद करते गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह

को छुड़ाने की योजना चन्द्रशेखर ने बनाई, पर बम जांचते वोहरा सहसा शहीद हो गए, घर में रखा बम दूसरे दिन फट जाने से योजना विफल हो गई, हमारी आजादी की नींव में उन सूरमाओं का इतिहास अमर है जिन्होंने हमें स्वाभिमान पूर्वक अपने इतिहास और संस्कृति की संरक्षा की अविचल प्रेरणा प्रदान की है।

27 फरवरी, 1931 के दिन चन्द्रशेखर आजाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी वहां अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। चन्द्रशेखर आजाद ने सुखदेव को तो भगा दिया पर खुद अंग्रेजों का अकेले ही सामना करते रहे, अंत में जब अंग्रेजों की एक गोली उनकी जांघ में लगी तो अपनी बंदूक में बची एक गोली को उन्होंने खुद ही मार ली और अंग्रेजों के हाथों मरने की बजाय खुद को ही समाप्त कर लिया। कहते हैं मौत के बाद अंग्रेजी अफसर और पुलिस वाले चन्द्रशेखर आजाद की लाश के पास जाने से भी डर रहे थे, चंद्रशेखर आजाद को वेश बदलने में बहुत माहिर माना जाता था, वह रूसी क्रांतिकारियों की कहानी से बहुत प्रेरित थे। चन्द्रशेखर आजाद की वीरता की कहानियाँ कई हैं जो आज भी युवाओं में देश प्रेम की लहर पैदा कर देती हैं, देश को अपने इस सच्चे वीर स्वतंत्रता सेनानी पर हमेशा गर्व रहेगा।

चन्द्रशेखर आजाद ने वीरता की नई परिभाषा लिखी। उनके बलिदान के बाद उनके द्वारा प्रारम्भ किया गया आन्दोलन और तेज हो गया, उनसे प्रेरणा लेकर हजारों युवक स्वतन्त्रता आन्दोलन में कूद पड़े। आजाद की शहादत के सोलह वर्षों बाद 15 अगस्त सन् 1947 को हिन्दुस्तान की आजादी का उनका सपना पूरा तो हुआ। परन्तु चन्द्रशेखर आजाद, आजाद भारत को देख न सके। ■

तिलकजी ने मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में समाचार पत्र प्रकाशित किये। मराठी व अंग्रेजी के दोनों समाचार पत्र राष्ट्रवादी विचारों के उद्घोषक बन गये। हिन्दू समाज की कुरीतियों के बारे में तिलकजी ने लेख लिखे। जन सामान्य में सामाजिक, राजनैतिक चेतना जागृत करने के लिए उन्होंने केसरी के माध्यम से सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाने का परामर्श दिया।



## सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रणेता तिलकजी

**सां**स्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतीक के नाते हम लोकमान्य तिलक का स्मरण करते हैं। इस महापुरुष का जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी में हुआ। गंगाधर शास्त्री और पार्वती बाई उनके माता-पिता थे। लोकमान्य गंगाधर तिलक की धार्मिक और संस्कृत की शिक्षा घर पर हुई। बाद में यह परिवार पूना चला आया। इनकी शिक्षा पूना के मराठी और इंग्लिश स्कूल से हुई। उच्च शिक्षा के लिए मुंबई के एलिफिस्टिन कॉलेज के विद्यार्थी बने उन्होंने संस्कृत में कविताएं भी कीं। ग्रेजुएट होने के बाद एलएलबी के अध्ययन काल में उन्होंने हिन्दू विधि शास्त्र का विशद अध्ययन किया। वे आगरकर के संपर्क में आये और न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। इसके बाद चिपलुनकर का सहयोग

मिला। तिलकजी ने मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में समाचार पत्र प्रकाशित किये। मराठी, अंग्रेजी के दोनों समाचार पत्र राष्ट्रवादी विचारों के उद्घोषक बन गये। दोनों समाचार पत्रों की सामग्री समान रहती थी।

हिन्दू समाज की कुरीतियों के बारे में तिलकजी ने लेख लिखे। जन सामान्य में सामाजिक, राजनैतिक चेतना जागृत करने के लिए उन्होंने केसरी के माध्यम से सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाने का परामर्श दिया। अभी तक महाराष्ट्र के घरों में गणेश पूजन की परम्परा थी। इस उत्सव के माध्यम से राजनैतिक आंदोलन को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने की पहल प्रारंभ हुई।

आज न केवल सार्वजनिक गणेशोत्सव महाराष्ट्र में वरन् पूरे देश में मनाया जाता है। संस्कृति के माध्यम से राष्ट्र चेतना का

अभियान तिलकजी ने सफल करके दिखाया।

1896-97 में महाराष्ट्र सहित मद्र, बिहार, पंजाब में भीषण अकाल पड़ा। प्लेग से लोग मरने लगे। लोगों को सहायता पहुंचाने में तिलक जी ने सक्रिय भूमिका निभाई, 1897 में महारानी विक्टोरिया के राज्यरोहण की हीरक जयंती मनाई गई। अधिकारी रैण्ड जिसने पूना में भेदभाव और ज्यादती की। 21 जून को पूना के गर्वमेंट हाउस में समारोह था।

कार्यक्रम की समाप्ति के बाद अंग्रेज अफसर रैण्ड टम-टम से चल पड़ा। इसके बाद लेफ्टिनेन्ट आयस्टन पत्नी के साथ दूसरी टम-टम से चला। रास्ते में उन पर पिस्तौल से गोलियां दागी गईं। जनता पर अत्याचार का बदला क्रांतिकारियों ने ले लिया। उस समय केसरी में भवानी की तलवार शीर्षक कविता प्रकाशित हुई, जिसका सारांश यह था कि दुष्टों को मारकर मैंने भूमि का भार कम किया, मैंने स्वराज्य स्थापना और स्वधर्म रक्षा से देश को मुक्त किया।

तिलकजी पर राजद्रोह का मुकदमा चला। उन्हें कारावास की सजा मिली। उनके ऊपर दूसरा राजद्रोह का मुकदमा लादा गया। उन्हें देश निकाला दिया गया रंगून माण्डले जेल में तिलकजी को रखकर यातनाएं दी गईं। जून 1914 से तिलकजी को माण्डले जेल से मुक्ति मिली। इसके बाद से पूरे देश ने तिलकजी को राष्ट्रनायक मान लिया। स्वतंत्रता का उद्घोष जो राष्ट्र चेतना का मंत्र बन गया। उससे यह जाहिर हो गया कि लोकमान्य तिलक प्रखर देशभक्त और राष्ट्रवादी नेता है। एक जनवरी 1917 को तिलकजी कानपुर गये, वहां उनका देवता के समान स्वागत हुआ, स्थान-स्थान पर उनकी आरती उतारी गई।

कानपुर के परेड ग्राउण्ड पर बीस हजार लोगों की सभा में उनका अभिनंदन किया गया। हिन्दी नहीं जानने के कारण उन्होंने अंग्रेजी में भाषण देते हुए दिव्य उद्घोष किया कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कांग्रेस में राष्ट्रवादी विचारों से नेतृत्व तिलक जी ने किया। उनके विचारों से क्रांतिकारियों ने भी प्रेरणा ली। संस्कृति से ही राष्ट्र चेतना प्रखर हो सकती है, इसलिए उन्होंने धार्मिक त्यौहारों को राजनैतिक जागृति का माध्यम बनाया। ■

# क्या है सेक्यूलरिज्म?

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात भारतवर्ष को एक सेक्यूलर स्टेट घोषित किया गया है तथा तबसे यह शब्द लोगों की जुबान पर इतना चढ़ गया है कि क्या बड़े-बड़े नेता और क्या गाँव-गाँव, गली-गली में बातचीत के स्वर को ऊँचा करके ही भाषण की हवस मिटाने वाले छुटभैये, सभी दिन में चार बार सेक्यूलर स्टेट की दुहाई देकर अपनी बात मनवाने का तथा दूसरों को उसके विरुद्ध बताकर गलत सिद्ध करने का प्रयास करते हैं।



पं. दीनदयाल उपाध्याय

**स्वतंत्रता** प्राप्ति के पश्चात भारत वर्ष को एक सेक्यूलर स्टेट घोषित किया गया है तथा तबसे यह शब्द लोगों की जुबान पर इतना चढ़ गया है कि क्या बड़े-बड़े नेता और क्या गाँव-गाँव, गली-गली में बातचीत के स्वर को ऊँचा करके ही भाषण की हवस मिटाने वाले छुट भैये, सभी दिन में चार बार सेक्यूलर स्टेट की दुहाई देकर अपनी बात मनवाने का तथा दूसरों

को उसके विरुद्ध बताकर गलत सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। सुनते-सुनते शब्द तो कानों में रम गया है, किंतु अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि भारत सरकार बोलने वाले नेता तथा सुनने वाली जनता सेक्यूलर शब्द का क्या अर्थ समझती हैं। विधान परिषद् में सेक्यूलर स्टेट का नाम लेने पर जब एक सदस्य ने पं. जवाहरलाल नेहरू से सेक्यूलर स्टेट का मतलब पूछा तो उन्होंने भी अर्थ बताने के स्थान पर सम्मानीय सदस्य को डॉटकर शब्द कोष देखने के लिए कहा। फलतः समस्या सुलझ नहीं पाई और आज भी लोग सेक्यूलर शब्द से भिन्न-भिन्न अर्थ लगाते हैं। सेक्यूलर के लिए भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त पर्यायों से यह भिन्नता स्पष्ट हो जाती है। लौकिक, धर्महीन, धर्मरहित, धर्मनिरपेक्ष,

अधार्मिक, अधर्मी, निधर्मी, असांप्रदायिक आदि अनेक शब्दों का सेक्यूलर के पर्याय इस नाते प्रयोग होता है। निश्चित ही उपर्युक्त सभी शब्द समानार्थक नहीं हैं। उनमें मत भिन्नता ही नहीं है अपितु वे विरोध की सीमा-रेखा को भी स्पर्श कर जाते हैं। अपने राज्य के स्वरूप के संबंध में इतना वैषम्य वास्तव में हितावह नहीं है। अच्छा हो कि हम सेक्यूलर शब्द के ठीक अर्थ समझ लें; कम से कम जिस अर्थ में हम भारत को सेक्यूलर स्टेट बनाना चाहते हैं, उसका तो निर्णय कर ही लेना चाहिए।

## रोमन साम्राज्य की प्रतिक्रिया

नेहरूजी के आदेशानुसार यदि डिक्शनरी का सहारा लिया जाए तो समस्या विशेष नहीं सुलझती, क्योंकि कोष में सेक्यूलर के अर्थ हैं अर्थात् अपना सौ वर्षों में एक बार होने वाला लौकिक। इनमें से लौकिक अर्थ सर्व साधारण व्यवहार में आता है तथा स्पिरिचुअल के विरोध में इसका प्रयोग होता है। सेक्यूलर स्टेट को कल्पना के विकास के पीछे भी यही भाव है। क्योंकि सेक्यूलर स्टेट की कल्पना का उदय पवित्र रोमन साम्राज्य के विरोध में से हुआ है। यूरोप के सभी देश किसी समय रोम के पोप के अधीन थे तथा प्रत्येक देश का राजा पोप के नाम पर ही शासन करता था। किंतु धीरे-धीरे रोमन कैथोलिक मत और पोप दोनों या इनमें से किसी एक के प्रति अविश्वास और विरोध की भावना बढ़ने लगी। फलतः प्रोटेस्टेंट मत का जन्म हुआ तथा फ्रांस की क्रांति के कारण और उसके परिणामस्वरूप जनता के घोष समानता और स्वतंत्रता और बंधुत्व हुए। साथ ही राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए ईसाई मत में अनेक चर्चों की स्थापना ईसाई मत के सामान्य जीवन पर घटते हुए प्रभाव ने पवित्र रोमन साम्राज्य को विघटित करके, ऐसे राज्य की कल्पना को जन्म दिया जिसमें सभी मतों के मानने वाले नागरिकता के समान अधिकारों का उपयोग कर सकें तथा राज्य जनता के मत में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। लोगों की दृष्टि अधिकाधिक भौतिकवादी होने के कारण लोगों की दृष्टि में राज्य का महत्व केवल लौकिक आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र रह गया है तथा आत्मा संबंधी सभी प्रश्नों की व्यक्तिगत इच्छा-अनिच्छा पर छोड़ देना उचित समझा।



## लौकिक और पारलौकिक

यूरोप में सेक्यूलर स्टेट की कल्पना के विकास का संक्षिप्त विवरण ऊपर दिया है। स्पिरिचुअल और टेंपोरल (सेक्यूलर) दो भिन्न-भिन्न क्षेत्र करके राज्य की ओर केवल सेक्यूलर आवश्यकताओं की पूर्ति का भार देकर भी यूरोप का कोई राज्य मत विशेष के पक्षपात की नीति से मुक्त नहीं हो पाया है। इंग्लैंड का राजा अभी भी (धर्मरक्षक) कहा जाता है तथा उसके लिए आवश्यक है कि वह मानने वाला प्रोटेस्टेंट ही हो, राज्य की ओर से गिरजे और पादरियों को वेतन और सहायता भी मिलती है। अमेरिका में भी प्रेसीडेंट के लिए शपथ लेते समय विशिष्ट धार्मिक विधि को पूरा करना आवश्यक है।

भारतवर्ष में वास्तविक रूप से तो राज्य की कल्पना के अंतर्गत लौकिक राज्य की ही कल्पना है। हमारे यहाँ धर्मगुरु को कभी राजा का स्थान नहीं मिला है। राजा स्वयं किसी भी मत का मानने वाला क्यों न हो, सदा सभी मतावलंबियों के प्रति न्याय और समानता का व्यवहार करता था। हाँ आज के सेक्यूलरिज्म की कल्पना के अनुसार पक्षपात रहित रहने का अर्थ किसी की मदद न करना नहीं था अपितु सबकी मदद करना था। अतः राज्य सब मतावलंबियों की समान रूप से सहायता करता था। इस सहायता के पीछे यह भाव निहित था कि प्रथम तो बिना पारलौकिक उन्नति के लौकिक उन्नति व्यर्थ है तथा दूसरे राजा का कर्तव्य है कि प्रजा की सब प्रकार की उन्नति का प्रबंध करे। और पारलौकिक क्षेत्र में यह प्रबंध सब मतों को समान सहायता देते हुए उनके आपसी संबंधों को सद्भावनापूर्ण बनाते हुए ही होता था। अतः किसी मत का राज्य न कायम करते हुए भी “यतो अयुदयनि श्रेयस प्राप्ति स धर्मः” की व्याख्या के अनुसार धर्म

का विकास करते हुए धर्मराज्य की अवश्य ही स्थापना की जाती थी।

## धर्म जीवन है

आज भारतवर्ष के नेतागण यद्यपि पश्चिमी आदर्शों को अपनाकर भावी भारत की रचना करना चाहते हैं और उसके अनुसार पश्चिम के अर्थ में सेक्यूलर स्टेट का अर्थ लौकिक राज्य ही लगाया जा सकता है, किंतु भारतीय जनता धर्मराज्य या रामराज्य की भूखी है और वह केवल लौकिक उन्नति में ही संतोष नहीं कर सकती। भारतीयता की स्थापना भी केवल एकांगी उन्नति से नहीं हो सकती क्योंकि हमने लौकिक और पारलौकिक उन्नति को एक दूसरे का पूरक ही नहीं तो एक दूसरे से अभिन्न माना है। किंतु पारलौकिक उन्नति के क्षेत्र में राज्य की ओर से किसी एक मत की कल्पना अनुचित होगी, अतः ऐसा वातावरण उत्पन्न करना होगा जिसमें सभी मत बढ़ सकें तथा एक सद्दिपाः बहुधा वदन्ति के सिद्धांत का पालन कर सकें। फलतः हमारे राज्य के लिए लौकिक राज्य सेक्यूलर स्टेट को ठीक पर्याय होने पर भी मौजूद नहीं होगा।

धर्म शब्द की उपर्युक्त परिभाषा एवं “धारणधर्ममित्याहुः धर्मोधारयते प्रजा” आदि परिभाषाओं के अनुसार यह शब्द अंग्रेजों के रिलीजन का पर्यायवाची न होकर उससे भिन्न है तथा व्यापक अर्थवाला है। हमारे यहाँ बिना धर्म के तो किसी के भाव की, उसके अस्तित्व की ही कल्पना कठिन है। फलतः हम समझते हैं कि हमारा राज्य धर्म को तिलांजलि नहीं दे सकता; अतः अधार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, धर्मरहित, धर्महीन, धर्म विरत आदि सभी शब्द न तो हमारे राज्य के आदर्शों को ही प्रकट करते हैं और न सेक्यूलर स्टेट ठीक पर्याय हो ही सकते हैं।

## मत और धर्म के भेद

अंग्रेजों के रिलीजन शब्द का पर्यायवाची शब्द यहाँ मत है तथा एक मत के माननेवाले को संप्रदाय कहा जाता है, जैसे शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, ख्रिस्ती संप्रदाय आदि। निश्चित ही पहले और आज भी राज्य इनमें से किसी एक संप्रदाय का नहीं हो सकता।

राज्य की दृष्टि से तो सबके लिए ही समान होनी चाहिए। फलतः हम कह सकते हैं कि राज्य को सांप्रदायिक न होकर असांप्रदायिक होना चाहिए। यही राज्य का सही आदर्श है। ऐसा राज्य किसी संप्रदाय विशेष के प्रति पक्षपात या किसी के प्रति घृणा का व्यवहार न करते हुए भी जीवन की लौकिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हुए धर्मराज्य हो सकता है।

## असांप्रदायिक कहें

असांप्रदायिक शब्द से राज्य के ठीक-ठीक आदर्श का ही बात नहीं होता अपितु सेक्यूलर के शाब्दिक नहीं तो पाश्चात्य व्यवहारिक अर्थ के भी यह बहुत निकट है। रूस को छोड़कर किसी राज्य ने कभी रिलीजन (मत) को समाप्त नहीं किया और आज तो रूस में भी पूजा स्वातंत्र्य को मान लिया है यद्यपि राज्य की ओर से किसी को कोई सुविधा नहीं मिलेगी। शेष सभी राज्यों में सभी संप्रदायों को अपने मत के द्वारा आत्मिक, शारीरिक स्वतंत्रता है तथा इंग्लैंड के राजा को छोड़कर शेष कहीं किसी संप्रदाय विशेष के प्रति पक्षपात नहीं है। अतः उन राज्यों को भी पवित्र रोमन साम्राज्य के विरोध में चाहे लौकिक समझा जाए, किंतु असांप्रदायिक कहना ही अधिक युक्ति संगत होगा। असांप्रदायिक शब्द के द्वारा हमारे नेताओं का अर्थ भी अधिक स्पष्ट होता है क्योंकि आज सेक्यूलर शब्द का प्रयोग केवल पाकिस्तान से, जिसने अपने आपको इस्लामी राज्य घोषित किया है भिन्नता दिखाना ही है। भारत इस्लामी राज्य के समान किसी एक संप्रदाय का राज्य नहीं है यही हमारे नेता प्रकट करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने सेक्यूलर शब्द को चुना है। आज यद्यपि सांप्रदायिक और राष्ट्रीय शब्दों का ठीक-ठीक ज्ञान न होने के कारण सेक्यूलर शब्द का नाम लेकर रेडियो से गीता और रामायण आदि का पाठ बंद करना आदि अनेक कार्य कर दिए जाते हैं। फिर भी भारतीय राज्य का आदर्श घोषित करते समय हमारे नेताओं के मस्तिष्क में जो प्रधान धारणा रही वह असांप्रदायिक शब्द से ही अधिक व्यक्त होती है। उपर्युक्त सभी कारणों में से असांप्रदायिक शब्द ही सेक्यूलर का निकटतम भाषांतर है और उसी का प्रयोग किया जाना चाहिए। ■



» भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आपातकाल की 50वीं बरसी पर मीसाबंदियों का सम्मान किया गया।



» भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी ने पत्रा में "मन की बात" सुना।



» प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने "मन की बात" सुना।



» मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा मध्यप्रदेश के नवनिर्वाचित संसद सदस्यों के साथ।



» मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने "एक पेड़ मां के नाम" अभियान में पौधारोपण किया।



» भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने "एक पेड़ मां के नाम" अभियान में पौधारोपण किया।



» प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने "एक पेड़ मां के नाम" अभियान में पौधारोपण किया।



» मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया।

“शक्ति हमारे असंयत व्यवहार में नहीं,  
बल्कि संयत कारवाई में निहित है”

दीनदयाल उपाध्याय



चरवेति

[www.charaveti.org](http://www.charaveti.org)